NYCS

RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com

अक्टूबर 2026, नई दिल्ली



ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज बनाने के रूस के प्रस्ताव से

सहकारी भंडारण को लगेंगे पंख

अंदर के पन्नों पर

सहकारी क्षेत्र में युवाओं को अवसर मुहैया कराने पर एनवाईसीएस का फोकस

सेवा के 25 साल और विकसित भारत का संकल्प

BRICS

INDRAPRASTHA GAS

IGL: India's Future Foreword Energy







Leading India's clean energy landscape

IGL believes in a customer-centric approach and provides clean energy solutions through innovative technology and diversification in India and abroad. IGL is playing a crucial role in the emerging scenario, in augmenting its compression capacity by adding new stations and investing in new-age fuels like Liquefied Natural Gas (LNG), Compressed Bio Gas (CBG) and Solar to address changing energy needs.

IGL's core deliverables include:

- IGL is a leading provider of clean and convenient Piped Natural Gas (PNG) and Compressed Natural Gas (CNG).
- IGL offers various services to meet the needs of Residential, Commercial and Industrial customers.
- IGL is a growing company, strongly committed to safety, innovation, and customer satisfaction.



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

An ISO 9001, ISO 14001 & OHSMS 45001 Certified Company

CIN No.: L23201DL1998PLC097614

World Trade Centre, Block G, 2nd Floor, Nauroji Nagar, New Delhi-110029, Website: www.iglonline.net

Follow us:

Customer Care

1800 102 5109 / 1800 180 5109 (24x7 Toll Free)

युवा सहकार

वर्ष : 03, अंक-04, अक्टूबर-2026

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता
दर्शन सोलंकी (विशेष आमंत्रित)
देवेन्द्र सिंह (विशेष आमंत्रित)
रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी (सीईओ)

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं फर्स्ट इंप्रेशन कॉरपोरेट सर्विस प्रा. लि., सेक्टर-63, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी द्वारा मुद्रित।

कार्यकारी संपादक: अभिषेक कुमार
पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia



सहकारी भंडारण से वैश्विक बाजार तक नए अवसर 04
आईसीए ग्लोबल बोर्ड में डायरेक्टर बने दिलीप संघाणी 05



06
ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज बनाने के रूस के प्रस्ताव से सहकारी भंडारण को लगेंगे पंख



18
सहकारी क्षेत्र में युवाओं को अवसर मुहैया कराने पर एनवाईसीएस का फोकस

एनवाईसीएस की केरल क्षेत्रीय बैठक का आयोजन 20
नए अवसर तलाश रहा नेफेड 21
पीएम की सेवा के 25 साल और विकसित भारत का संकल्प 22
शी मार्ट की शुरुआत, सशक्त होंगी महिलाएं 24
राजस्थान की डेयरी कोऑपरेटिव को मिलेगी नई रफ्तार 26
बस्तर से सहकारिता की नई इबारत 28
भारत टैक्सी 31 शहरों तक पहुंची 30
तीरंदाजों, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी टीमों ने रखी लाज 32
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद कृभको ने दिखाया दम 34

सहकारी भंडारण से वैश्विक बाजार तक नए अवसर



वैज्ञानिक भंडारण और वैश्विक बाजार के बीच सेतु बनकर सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती हैं। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की परिकल्पना इसी संभावना को आगे बढ़ाने का अवसर है जहां पैक्स केवल गांव की कृषि संस्था नहीं, बल्कि किसान और बाजार के बीच एक सक्षम आर्थिक भागीदार बन सके।

सहकारी समितियां लंबे समय से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला रही हैं। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने से लेकर खाद, बीज और कृषि संबंधी सेवाएं पहुंचाने तक इन संस्थाओं ने गांवों में आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। बदलते कृषि परिदृश्य में सहकारी समितियों की भूमिका को एक नए स्तर पर ले जाने का अवसर सामने आया है। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की प्रस्तावित पहल और देश की विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना का बेहतर समन्वय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को कृषि व्यापार की व्यापक मूल्य श्रृंखला से जोड़ सकता है।

रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की ओर से प्रस्तावित ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की परिकल्पना ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच खाद्यान्न व्यापार को सुगम बनाने की है। यदि यह पहल ठोस आकार लेती है, तो भारतीय सहकारी समितियों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि, इस प्रस्ताव को देश की सहकारी भंडारण योजना से जोड़ने के लिए अभी संस्थागत समन्वय, व्यापार नियमों और तकनीकी व्यवस्थाओं पर काम किया जाना बाकी है।

देश में पैक्स के स्तर पर विकसित हो रहे गोदाम किसानों की उपज को सुरक्षित रखने, स्थानीय खरीद और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने तथा कृषि उपज के विपणन में मदद कर सकते हैं। यदि भविष्य में इस भंडारण व्यवस्था को ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की व्यापार प्रणाली से जोड़ने के लिए आवश्यक मानक, प्रमाणन और डिजिटल सुविधाएं विकसित की जाती हैं, तो सहकारी समितियों के पास व्यापक बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर होगा।

इस संभावित तालमेल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे गांवों में निर्मित कृषि अवसंरचना का उपयोग केवल घरेलू भंडारण तक सीमित नहीं रहेगा। गुणवत्ता मानकों और पारदर्शी व्यापार व्यवस्था के अनुरूप तैयार गोदाम अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने की संभावना भी पैदा कर सकते हैं। इससे पैक्स की व्यावसायिक भूमिका का विस्तार हो सकता है और किसानों को अपनी उपज के विपणन के अधिक विकल्प मिल सकते हैं।

हालांकि, यह संभावना अभी भविष्य की दिशा है। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के संचालन संबंधी नियम, सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रक्रियाएं, भुगतान प्रणाली और लॉजिस्टिक्स का ढांचा विकसित होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि भारतीय सहकारी समितियां इसमें किस तरह भागीदारी कर सकेंगी।

किसान की आर्थिक स्थिति केवल उत्पादन पर निर्भर नहीं करती। फसल को कब और किस बाजार में बेचा जाए, यह भी उसकी आय को प्रभावित करता है। गांव के पास वैज्ञानिक गोदाम उपलब्ध होने पर किसान को फसल कटाई के तुरंत बाद उपज बेचने की मजबूरी से राहत मिल सकती है। वहीं, सहकारी समितियां भंडारण और उपज के बदले वित्तीय सहायता जैसी सेवाओं के माध्यम से किसानों की बाजार संबंधी जरूरतों में सहयोग कर सकती हैं। यदि भविष्य में पैक्स के गोदामों को मानकीकृत गुणवत्ता परीक्षण, ग्रेडिंग, वेयरहाउस रसीद और डिजिटल व्यापार प्रणाली से जोड़ा जाता है, तो सहकारी समितियां अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार के लिए भी उपयोगी आधार बन सकती हैं। इससे किसानों की उपज को नए बाजारों तक पहुंचाने और सहकारी संस्थाओं की व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के रास्ते खुल सकते हैं।

वैज्ञानिक भंडारण और वैश्विक बाजार के बीच सेतु बनकर सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती हैं। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की परिकल्पना इसी संभावना को आगे बढ़ाने का अवसर है जहां पैक्स केवल गांव की कृषि संस्था नहीं, बल्कि किसान और बाजार के बीच एक सक्षम आर्थिक भागीदार बन सके।

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

आईसीए ग्लोबल बोर्ड में डायरेक्टर बने दिलीप संघाणी

युवा सहकार टीम



भारतीय सहकारिता आंदोलन के लिए 15 सितंबर, 2026 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। इस तारीख को अब भारतीय सहकारिता आंदोलन के लिए सम्मान और वैश्विक सहकारिता के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव के प्रतीक के रूप याद किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि इफको और गुजकामासोल के चेयरमैन दिलीप संघाणी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) के ग्लोबल बोर्ड में एट-लार्ज डायरेक्टर के रूप में चुने गए हैं। इस पद पर पहुंचने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले आदित्य यादव आईसीए बोर्ड के डायरेक्टर बने थे। जबकि हर्ष मुकेश भाई संघाणी लगातार दूसरी बार आईसीए यूथ कमेटी के प्रेसीडेंट चुने गए हैं। इस नाते उन्हें आईसीए के ग्लोबल बोर्ड में जगह मिली है। यह भारतीय सहकारिता जगत के लिए गर्व का पल है।

15 सितंबर को पनामा सिटी के पनामा कन्वेंशन सेंटर में आयोजित आईसीए की महासभा में वर्ष 2026-2030 के लिए नए ग्लोबल बोर्ड का गठन किया गया। एट-लार्ज डायरेक्टर के 15 पदों के लिए 24 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इस चुनाव में दिलीप संघाणी को 526 वोट मिले। वे भारत के एकमात्र उम्मीदवार थे। 526 वोटों के साथ संघाणी ने कुल उम्मीदवारों में तीसरा सबसे अधिक वोट हासिल किया और एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप के उम्मीदवारों में सर्वाधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार बने। आईसीए ग्लोबल बोर्ड में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष, चार क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, आठ सेक्टोरल संगठनों के प्रतिनिधि, यूथ एवं जेंडर इक्वैलिटी कमेटियों के अध्यक्ष और आईसीए के सदस्यों द्वारा सीधे निर्वाचित 15 एट-लार्ज डायरेक्टर शामिल होते हैं।

दिलीप संघाणी लंबे समय से सहकारिता क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। आईसीए के वैश्विक निदेशक मंडल में उनका चुना जाना भारतीय सहकारिता आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी तरह, हर्ष संघाणी ने आईसीए के वैश्विक निदेशक मंडल तक पहुंचने का रास्ता आईसीए युवा समिति के माध्यम से हासिल किया।



हर्ष संघाणी लगातार दूसरी बार बने आईसीए यूथ कमेटी के प्रेसीडेंट

हर्ष संघाणी को जुलाई 2025 में मैनचेस्टर (यूके) में आयोजित आईसीए यूथ कमेटी की वार्षिक पूर्ण बैठक में पहली बार अध्यक्ष चुना गया था। इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले भारतीय थे। पनामा सिटी में आयोजित युवा महासभा में उन्हें एक बार फिर आईसीए यूथ कमेटी का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। इसके साथ वे वर्ष 2026-2030 के लिए नए आईसीए वैश्विक निदेशक मंडल में युवा प्रतिनिधि के रूप में बने रहे। उनकी यह भूमिका अंतरराष्ट्रीय सहकारिता आंदोलन में युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

दिलीप संघाणी और हर्ष संघाणी की आईसीए में मौजूदगी की खास बात यह है कि दोनों अलग-अलग चुनावी प्रक्रियाओं और अलग-अलग प्रतिनिधित्व श्रेणियों के माध्यम से वैश्विक निदेशक मंडल तक पहुंचे हैं। आईसीए दुनिया भर के सहकारी संगठनों का प्रमुख वैश्विक मंच है। इसके वैश्विक निदेशक मंडल में भारत के दो प्रतिनिधियों की मौजूदगी से भारतीय सहकारिता क्षेत्र को वैश्विक नीतिगत चर्चा, सहकारी विकास और युवा सहभागिता से जुड़े विषयों पर सीधे योगदान का अवसर मिला है। ■



ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज बनाने के रूस के प्रस्ताव से

सहकारी भंडारण को लगेंगे पंख

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने रखा ग्रेन एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव

दुनिया के सबसे पुराने कमोडिटी एक्सचेंज शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की तर्ज पर बन सकता है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज

ब्रिक्स देशों के बीच हो सकेगा खाद्यान्न का कारोबार, ज्यादा और कम पैदावार वाले देशों को होगा फायदा

सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

पिछले महीने 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संगठन के प्रमुख सदस्य देश रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज बनाने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर ब्रिक्स देशों के बीच बनी सहमति भारत के सहकारी क्षेत्र की विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है। ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणापत्र में ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की स्थापना से जुड़ी पहल को आगे बढ़ाने और इसके संचालन के तौर-तरीकों पर चर्चा जारी रखने की बात कही गई है। भविष्य में इस प्लेटफॉर्म का दायरा अन्य कृषि उत्पादों तक बढ़ाने की संभावना भी घोषणापत्र में जताई गई है। इस पहल से ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों को सीधा लाभ मिलेगा। जिन देशों में कृषि पैदावार उनकी खपत से ज्यादा है या जिन्हें अनाज आयात की दरकार पड़ती है, सभी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

भारतीय संदर्भ में इसे देखें तो घरेलू कृषि क्षेत्र को इसका बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही, सहकारी क्षेत्र की अनाज भंडारण योजना को इससे बल मिलेगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी

अन्न भंडारण योजना है जिनका संचालन प्राथमिक सहकारी समितियां (पैक्स) सहित अन्य सहकारी समितियां कर रही हैं। अभी यह योजना के निर्माण के विभिन्न चरणों में है। ग्रेन एक्सचेंज से भारतीय कृषि उत्पादों को नया बाजार मिलेगा जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। रूस के राष्ट्रपति की ओर से प्रस्तावित ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की परिकल्पना ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है जहां सदस्य देशों के उत्पादक और खरीदार अपेक्षाकृत सीधे कारोबार कर सकें। हालांकि इसकी ढांचागत संरचना, व्यापार नियम, भुगतान व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कई मुद्दों पर अभी आगे काम होना है। भारतीय सहकारिता क्षेत्र के लिए यह एक वरदान साबित हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एव सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने पहले से ही बड़े स्तर पर वैज्ञानिक अनाज भंडारण क्षमता विकसित करना शुरू कर दिया है। इसके तहत देश में सात करोड़ टन अतिरिक्त अनाज भंडारण की क्षमता विकसित की जानी है। यह दायित्व केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को दिया गया है। जुलाई 2026 तक देश में इस योजना के तहत 1,015 प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) की पहचान कर ली गई थी। जबकि 313 पैक्स ने अपने गोदामों का निर्माण कार्य पूरा भी कर लिया है। इसके तहत अब तक 1.80 लाख टन से अधिक नई क्षमता तैयार हो चुकी है।

इस योजना के तहत पैक्स को केवल गोदाम तक सीमित नहीं रखा गया है। उन्हें खरीद केंद्र, प्रसंस्करण इकाई, कस्टम हायरिंग सेंटर और अन्य कृषि सेवाओं से जोड़ने की भी व्यवस्था की गई है। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के दायरे में भी ये गतिविधियां शामिल की गई हैं। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर भंडारण क्षमता को बढ़ाना, किसानों की मजबूरी में बिक्री को घटाना, परिवहन (ढुलाई) लागत घटाना और पैक्स को बहुउद्देशीय आर्थिक इकाइयों में बदलना है।

गुणवत्ता और पारदर्शिता जरूरी

भंडारण क्षमता बढ़ाने के साथ अनाज की गुणवत्ता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। योजना के तहत गोदामों के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन आवश्यक है। भंडारण सुविधाओं को वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के मानकों और स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया जाना है। अनाज को खराब होने से बचाने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन और आवश्यक सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया गया है। गोदाम निर्माण कार्यों की नियमित जांच और गुणवत्ता ऑडिट का प्रावधान है। पैक्स के सदस्यों को परियोजना की निगरानी में भागीदारी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि परियोजना प्रबंधन सलाहकार निर्माण और खर्च से जुड़े अपडेट उपलब्ध कराते हैं। योजना के तहत गोदामों के लिए एक समान ब्रांडिंग भी निर्धारित की गई है। स्वीकृत 'ग्रेन स्टोरेज लोगो' और निर्धारित रंग योजना के माध्यम से इस पहल की एक अलग पहचान बनाने का प्रयास किया गया है।

शिकागो एक्सचेंज की तर्ज पर ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज

शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबीओटी दुनिया के सबसे पुराने और प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंजों में से एक है। यहां गेहूं, मक्का, सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल और अन्य कृषि जिंसों का वायदा कारोबार होता है। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के संदर्भ में सीबीओटी मॉडल महत्वपूर्ण है। इसे इस तरह समझ सकते हैं। सीबीओटी में किसान, व्यापारी, प्रोसेसर और बाजार के अन्य भागीदार भविष्य की कीमतों के जोखिम को हेज कर सकते हैं। गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों के भाव वैश्विक बाजार के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ मूल्य बनते हैं। ब्रिक्स देशों द्वारा अगर इस मॉडल को व्यापक रूप दिया जाता है तो ब्रिक्स देश अनाज व्यापार के लिए अपना अलग प्लेटफॉर्म विकसित कर सकते हैं। इससे सदस्य देशों के बीच वैश्विक बाजार की तुलना में अपने लिए नई कीमतें निर्धारित करने, व्यापार समझौता, वेयरहाउसिंग, गुणवत्ता मानक और परिवहन का नया ढांचा विकसित होने की संभावना है।

ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज को अगर अनाज भंडारण योजना के माध्यम से पैक्स के गोदामों, वेयरहाउस रसीद, ग्रेडिंग और

ग्रेन एक्सचेंज से भारतीय कृषि उत्पादों को नया बाजार मिलेगा जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। रूस के राष्ट्रपति की ओर से प्रस्तावित ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की परिकल्पना ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है जहां सदस्य देशों के उत्पादक और खरीदार अपेक्षाकृत सीधे कारोबार कर सकें। हालांकि इसकी ढांचागत संरचना, व्यापार नियम, भुगतान व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कई मुद्दों पर अभी आगे काम होना है। भारतीय सहकारिता क्षेत्र के लिए यह एक वरदान साबित हो सकती है।



शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबीओटी दुनिया के सबसे पुराने और प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंजों में से एक है। सीबीओटी में किसान, व्यापारी, प्रोसेसर और बाजार के अन्य भागीदार भविष्य की कीमतों के जोखिम को हेज कर सकते हैं। ब्रिक्स देशों द्वारा अगर इस मॉडल को व्यापक रूप दिया जाता है तो ब्रिक्स देश अनाज व्यापार के लिए अपना अलग प्लेटफॉर्म विकसित कर सकते हैं। इससे सदस्य देशों के बीच वैश्विक बाजार की तुलना में अपने लिए नई कीमतें निर्धारित करने, व्यापार समझौता, वेयरहाउसिंग, गुणवत्ता मानक और परिवहन का नया ढांचा विकसित होने की संभावना है।

गुणवत्ता परीक्षण के अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार तंत्र से जोड़ा जाता है तो गांव स्तर की सहकारी भंडारण व्यवस्था केवल अनाज रखने की जगह नहीं, बल्कि कृषि व्यापार इन्फ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन सकती है। हालांकि, अभी ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज और भारत की सहकारी भंडारण योजना के बीच किसी औपचारिक समझौते की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रस्तावित एक्सचेंज के व्यापार नियम, गुणवत्ता मानक, भुगतान व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स ढांचा किस रूप में विकसित होता है।

पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नए केंद्र

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी हो रही है, उतनी ही तेजी से खाद्यान्न के सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण की जरूरत भी बढ़ रही है। खेतों में बढ़ता उत्पादन तभी किसान और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए वास्तविक ताकत बन सकता है, जब उसे सही समय पर सुरक्षित रखा जा सके और किसान को अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सहकारिता के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की व्यवस्था खड़ी करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल आगे बढ़ रही है। वर्ष 2023 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य केवल गोदाम बनाना नहीं, बल्कि पैक्स को भंडारण, प्रसंस्करण, खरीद और वितरण से जोड़कर उन्हें एकीकृत ग्रामीण सेवा केंद्रों के रूप में विकसित करना है।

यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में कृषि उत्पादन का बड़ा हिस्सा गांवों में होता है, जबकि भंडारण और बाजार की सुविधाएं उत्पादन केंद्र से दूर होती हैं। ऐसे में किसान को फसल कटाई के तुरंत बाद उसे बेचने का दबाव रहता है। स्थानीय स्तर पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध होने पर किसान अपनी उपज को सुरक्षित रख सकता है और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार बिक्री का निर्णय ले सकता है।

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका केंद्र केवल गोदाम नहीं, बल्कि पैक्स और अन्य सहकारी समितियां हैं। पैक्स लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अल्पावधि ऋण और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के रूप में काम करती रही हैं। अब इन्हें कृषि अवसंरचना और मूल्य श्रृंखला से जोड़कर उनकी भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। योजना के तहत पैक्स स्तर पर भंडारण के साथ-साथ प्राथमिक प्रसंस्करण, खरीद, वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि मशीनरी की सुविधा विकसित करने का प्रावधान है। कस्टम हायरिंग सेंटर

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
लाया है

देहरादून शहर में पहले आओं पहले पाओं स्कीम के तहत
अपने घर का सपना पूरा करने का एक सुनेहरा मौका।

एम.डी.डी.ए. की ट्रांसपोर्ट नगर फेस–2, आई.एस.बी.टी. एवं आमवाला तरला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून की आवसीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित आय वर्ग के लोगों हेतु पंजीकरण प्रारम्भः–

HIG | MIG | STUDIO APARTMENT | L.I.G.





क्र. स.	फ्लैटों की श्रेणी	अनुमानित कीमत रू लाख में।	पंजीकरण धनराशि रू लाख में।	फ्लैट का अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग फीट)	फ्लैटों की संख्या
1.	अल्प आय वर्ग (LIG) आलयम, सहस्त्रधारा रोड़	22.90	2.30	582.82	60
2.	अल्प आय वर्ग (LIG 'C' Block) आलयम, सहस्त्रधारा रोड़	23.29	2.32	582.82	16
3.	मध्यम आय वर्ग (MIG) आलयम, सहस्त्रधारा रोड़	65.85	6.59	1503.40	112
4.	उच्च आय वर्ग (HIG) आलयम, सहस्त्रधारा रोड़	75.64	7.57	1877.83	112

क्र. स.	फ्लैटों की श्रेणी	अनुमानित कीमत रू लाख में।	पंजीकरण धनराशि रू लाख में।	फ्लैट का अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग फीट)	फ्लैटों की संख्या
5.	स्टूडियो अपार्टमेन्ट आलयम, सहस्त्रधारा रोड़	32.29	3.23	798.18	48
6.	अल्प आय वर्ग (LIG) ट्रांसपोर्ट नगर, फेज–2	19.90	2.00	453.53	97
7.	मध्यम आय वर्ग (MIG) ट्रांसपोर्ट नगर, फेज–2	49.50	4.95	1090	27
8.	उच्च आय वर्ग (HIG) आई.एस.बी.टी.	71.50	7.15	1954	130

विशेष छूट :–

1. उक्त भवनों में एक मुश्त धनराशि जमा किये जाने पर 02 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
2. यदि काई महिला/सिनियर सिटिजन/दिव्यांग इस हेतु आवेदन करे तो उनको 01 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट उनको पूर्ववत 02 प्रतिशत की छूट प्रदान करने के उपरान्त अवशेष देय धनराशि प्रदान की जायेगी।

आलयम आवसीय योजना
की जानकारी हेतु
मो. **8006409136**

आई.एस.बी.टी./ट्रांसपोर्ट नगर
आवसीय योजना की जानकारी हेतु
मो. **9193639595**

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

सहारनपुर रोड़, ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून। फोन : 0135-663150
E mail: info.mdda@mddaonline.in Website : www.mddaonline.in
पंजीकरण फॉर्म प्राधिकरण के साइट ऑफिस, कार्यालय व नीचे दिये गए बैंक की शाखाओं में भी उपलब्ध है।

सहकारिता से खाद्य सुरक्षा

इस पूरी पहल की संस्थागत संरचना भी इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति के अनुरूप है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर-मंत्रालयी समिति इसकी निगरानी करती है, वहीं राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की सहकारी समितियां योजना के क्रियान्वयन और समन्वय में सहयोग करती हैं। जिन क्षेत्रों में भंडारण की आवश्यकता है, वहां जिला सहकारी विकास समितियों के माध्यम से पैक्स की पहचान की जाती है। भूमि की उपयुक्तता, स्वामित्व और सदस्यों की सहमति जैसे पहलुओं को भी परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस योजना का लक्ष्य खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था को केवल बड़े केंद्रीय गोदामों तक सीमित रखने की बजाय उसे गांवों और उत्पादन केंद्रों के करीब ले जाना है।

अगर ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव जल्द ही आकार लेता है तो यह न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि यहां के किसानों और सहकारिता क्षेत्र के लिए बड़े बदलाव की कहानी लिखेगा।

ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज को अगर अनाज भंडारण योजना के माध्यम से पैक्स के गोदामों, वेयरहाउस रसीद, ग्रेडिंग और गुणवत्ता परीक्षण के अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार तंत्र से जोड़ा जाता है तो गांव स्तर की सहकारी भंडारण व्यवस्था केवल अनाज रखने की जगह नहीं, बल्कि कृषि व्यापार इन्फ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन सकती है। हालांकि, अभी ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज और भारत की सहकारी भंडारण योजना के बीच किसी औपचारिक समझौते की घोषणा नहीं हुई है।

के माध्यम से पैक्स ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर और दूसरी कृषि मशीनरी किसानों को किराये पर उपलब्ध करा सकते हैं। वहीं प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां अनाज की सफाई, छंटाई और सुखाने जैसी गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर संभव बनाएंगी। इस तरह पैक्स की भूमिका केवल ऋण देने वाली संस्था तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह किसान के लिए उत्पादन से लेकर भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार तक की श्रृंखला में भागीदार बन रही है।

बढ़ता उत्पादन, बढ़ती भंडारण जरूरत

देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025-26 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 37.65 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 35.77 करोड़ टन से लगभग 1.88 करोड़ टन अधिक है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाने के लिए भी मजबूत भंडारण व्यवस्था आवश्यक है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्यों की एजेंसियों की केंद्रीकृत भंडारण व्यवस्था देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन खाद्यान्न को उत्पादन केंद्र के आसपास ही सुरक्षित रखने वाली विकेंद्रीकृत व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। यही वह क्षेत्र है जहां सहकारी संस्थाएं विशेष भूमिका निभा सकती हैं।

यदि किसान के गांव या उसके आसपास ही गोदाम उपलब्ध हो, तो फसल को दूर स्थित भंडारण केंद्र तक ले जाने का खर्च कम होता है। खरीद केंद्रों और भंडारगृहों के बीच परिवहन लागत घटती है, अनाज की बबार्दी कम होती है और स्थानीय स्तर पर कृषि मूल्य श्रृंखला मजबूत होती है। इसी उद्देश्य से विकेंद्रित अनाज भंडारण योजना को शुरू किया गया है। योजना का लक्ष्य खाद्यान्न की बबार्दी कम करना, किसानों को जल्दबाजी में बिक्री से बचाना, परिवहन लागत घटाना, पैक्स की भूमिका का विस्तार करना और किसानों के लिए अधिक आय के अवसर तैयार करना है।

सरकारी योजनाओं का एकीकृत मॉडल

इस पहल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न सरकारी योजनाओं का समन्वय है। विकेंद्रित अनाज भंडारण योजना को कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जैसी योजनाओं से जोड़ा गया है। कृषि अवसंरचना कोष फसल कटाई के बाद की अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता तथा ब्याज में छूट उपलब्ध कराता है। कृषि विपणन अवसंरचना योजना के तहत भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए पूंजीगत सब्सिडी की व्यवस्था है। कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन के माध्यम से कृषि मशीनरी तक पहुंच बढ़ाने और कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन

योजना स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करती है। इन योजनाओं का एक साथ आना पैक्स को एक ऐसे ग्रामीण सेवा केंद्र में बदलने की संभावना पैदा करता है जहां किसान को एक ही संस्थागत ढांचे के भीतर कई सेवाएं मिल सकें।

व्यावहारिक वित्तीय मॉडल

किसी भी ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना की सफलता केवल उसके निर्माण पर निर्भर नहीं करती। उसके लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य मॉडल भी जरूरी है। इस योजना में इसी पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना के तहत कृषि विपणन अवसंरचना योजना की सब्सिडी को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33.33 प्रतिशत किया गया है। वहीं मार्जिन मनी की आवश्यकता को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है। पात्र परियोजनाओं के लिए ब्याज सहायता और ऋण सहायता की व्यवस्था भी की गई है। नाबार्ड पात्र परियोजनाओं के लिए सब्सिडी देने वाली एजेंसी के रूप में काम करता है, जबकि राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पैक्स के लिए प्रमुख ऋणदाता संस्थानों की भूमिका निभाते हैं। इस योजना में नाबार्ड की विशेष पुनर्वित्त सुविधा और कृषि अवसंरचना कोष के तहत मिलने वाली 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मिलाकर पैक्स के लिए प्रभावी ऋण ब्याज दर 1 प्रतिशत तक हो गई है। इसके अलावा पात्र गोदामों को निर्धारित शर्तों के साथ एफसीआई द्वारा किराये पर लेने की व्यवस्था ने भी परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को मजबूत किया है।

नेरपिंगलाई पैक्स बड़ा उदाहरण

इस योजना का वास्तविक प्रभाव समझने के लिए महाराष्ट्र के अमरावती स्थित नेरपिंगलाई पैक्स का उदाहरण महत्वपूर्ण है। इस पैक्स ने योजना के तहत 3,000 टन क्षमता वाला गोदाम तैयार किया है। परियोजना को कृषि



विपणन अवसंरचना और कृषि अवसंरचना कोष से सहायता मिली। नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता के कारण परियोजना के लिए प्रभावी ऋण ब्याज दर 1 प्रतिशत तक रही। इस गोदाम में लगभग 300 किसान सोयाबीन की करीब 32,000 बोरियां जमा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति ने जमा की गई उपज के बदले लगभग 4.50 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि किसानों को उपलब्ध कराई। इससे किसानों को फसल कटाई के बाद तत्काल कम कीमत पर अपनी उपज बेचने की मजबूरी से बचने में मदद मिली।

दूसरी ओर पैक्स के लिए भी यह परियोजना आय का नया स्रोत बन रही है। समिति को किराए से सालाना लगभग 7.68 लाख रुपये और वार्षिक ब्याज आय से करीब 54 लाख रुपये की आय हो रही है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। सहकारी भंडारण मॉडल किसान और पैक्स दोनों के लिए आर्थिक अवसर तैयार कर रहे हैं।

देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025-26 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 37.65 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 35.77 करोड़ टन से लगभग 1.88 करोड़ टन अधिक है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाने के लिए भी मजबूत भंडारण व्यवस्था आवश्यक है।



कस्टम हायरिंग सेंटर से कृषि मशीनरी की उपलब्धता बढ़ती है। खरीद केंद्र से किसानों को स्थानीय स्तर पर अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलता है। उचित दर की दुकानों और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की बिक्री से सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों का दायरा बढ़ सकता है।

गांव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा

विकेंद्रित भंडारण का असर केवल अनाज तक सीमित नहीं है। इसके साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कई दूसरे हिस्से भी जुड़ रहे हैं। जब स्थानीय स्तर पर गोदाम बनता है, तो परिवहन की जरूरतों में बदलाव आता है। प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई बनने से स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन होता है। कस्टम हायरिंग सेंटर से कृषि मशीनरी की उपलब्धता बढ़ती है। खरीद केंद्र से किसानों को स्थानीय स्तर पर अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलता है। उचित दर की दुकानों और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की बिक्री से सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों का दायरा बढ़ सकता है। इस तरह एक गोदाम धीरे-धीरे ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों को जोड़ने वाला केंद्र बन रहा है।■

किसान से बाजार तक मजबूत कड़ी

कृषि क्षेत्र में किसान की आय केवल उत्पादन की मात्रा से तय नहीं होती। फसल कब बेची जाए, कहां बेची जाए और उसे बेचने से पहले कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है– ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय भंडारण किसान को समय का विकल्प देता है। यह विकल्प ही कई बार किसान की सौदेबाजी की क्षमता को मजबूत करता है। जब किसान को फसल कटते ही बेचने की मजबूरी कम होती है, तो वह बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेने की स्थिति में आता है। इसीलिए विकेंद्रित भंडारण को केवल अवसंरचना निर्माण की योजना के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को कृषि मूल्य श्रृंखला में अधिक सक्रिय बनाने की दिशा में भी एक कदम है।

डेटा सेंटर बन रहे भारत की नई डिजिटल फैक्ट्री



युवा सहकार टीम

मोबाइल फोन से पेमेंट करते समय हमें शायद ही कभी यह ख्याल आता है कि हमारी रिक्वेस्ट आखिर जाती कहां है। ऑनलाइन बैंकिंग से बैलेंस देखना हो, रेलवे टिकट बुक करना हो, सरकारी पोर्टल से प्रमाणपत्र डाउनलोड करना हो, ऑनलाइन खरीदारी करनी हो, वीडियो देखना हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से कोई सवाल पूछना हो, इन सभी सेवाओं के पीछे डेटा सेंटर की बड़ी भूमिका है।

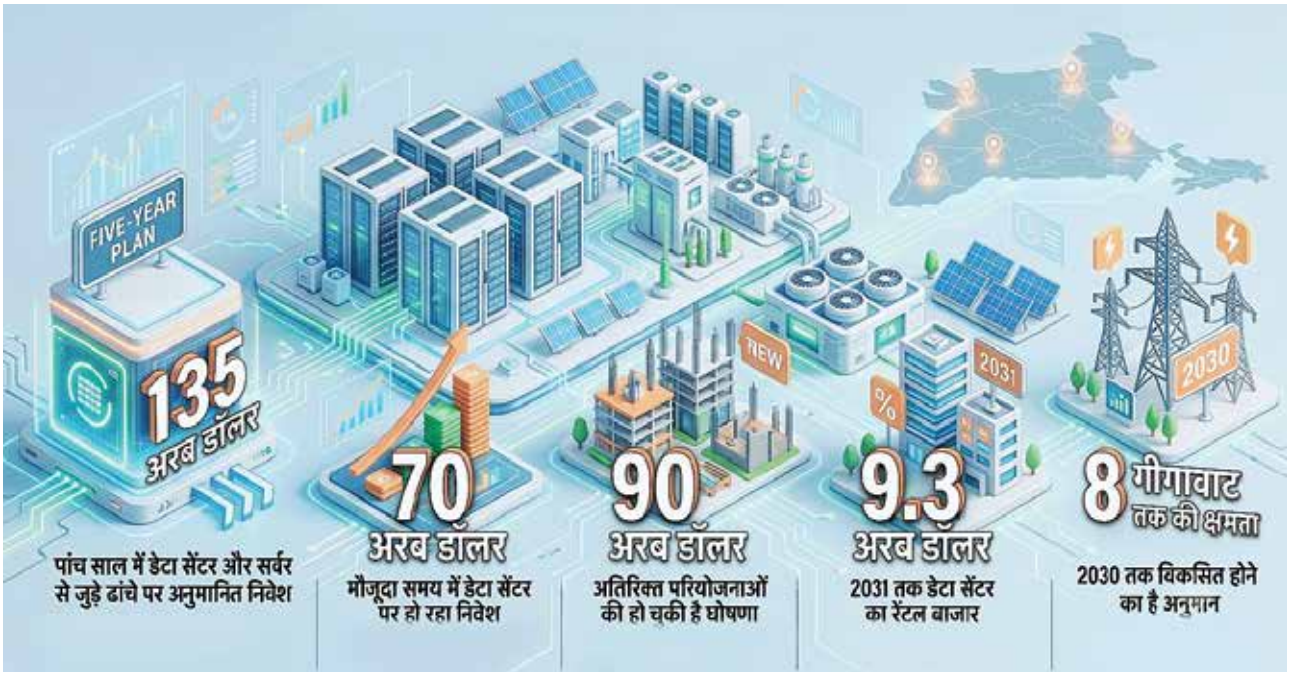
डेटा सेंटर को डिजिटल अर्थव्यवस्था की विशाल फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां सामान्य उत्पादों की जगह डेटा का स्टोरेज, प्रोसेसिंग और ट्रांसफर होता है। भारत में डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के कारण अब इन डेटा सेंटरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसका प्रभाव केवल आईटी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहने वाला है। बिजली, कूलिंग, निर्माण, रियल एस्टेट, केबल, जनरेटर, लॉजिस्टिक्स, साइबर सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में इससे नई आर्थिक गतिविधियां शुरू होने की संभावना है।

रोजगार के मिलेंगे लाखों अवसर

भारत में बढ़ते डेटा सेंटर का सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ने की संभावना है। सक्वायर यार्डस की अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रस्तावित करीब 9,030 मेगावाट के डेटा सेंटर्स वर्ष 2030 तक लगभग 4.33 लाख नौकरियों के अवसर पैदा कर सकते हैं। इस आंकड़े में केवल डेटा सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं। निर्माण, बिजली व्यवस्था, फाइबर नेटवर्क, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और मेंटेनेंस जैसी सहायक गतिविधियों से जुड़े रोजगार भी इसका हिस्सा होंगे। केंद्र सरकार

AI और क्लाउड की बढ़ती जरूरत से तेज होगा विस्तार, इंजीनियर से इलेक्ट्रिशियन और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए खुलेंगे रोजगार के रास्ते

9,030 मेगावाट के देशभर में विकसित हो रहे डेटा सेंटर्स से 2030 तक 4.33 लाख रोजगार मिलने की है संभावना



डेटा सेंटर रोजगार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके लिए सिर्फ आईटी विशेषज्ञों की जरूरत नहीं होती। डेटा सेंटर के डिजाइन और चलाने के लिए इलेक्ट्रकल इंजीनियर,मैकेनिकल इंजीनियर नेटवर्क इंजीनियर क्लाउड इंजीनियर, सर्वर इंजीनियर साईबर स्पेशलिस्ट डेटा सेंटर टेकनिशियन और फेसिलिटी मैनेजर जैसे लोगों की जरूरत होती है। एआई के विस्तार से रोजगार का एक नया वर्ग भी तैयार हो रहा है।

का एक अन्य अनुमान हाई-स्किल रोजगार की तस्वीर सामने रखता है। मई 2026 में सरकार ने कहा था कि डेटा सेंटर क्षेत्र के विस्तार से वर्ष 2030 तक एआई सिस्टम, कूलिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब एक लाख इंजीनियरिंग नौकरियां पैदा हो सकती हैं। एक लाख का आंकड़ा मुख्य रूप से तकनीकी और इंजीनियरिंग नौकरियों को दर्शाता है, जबकि 4.33 लाख का अनुमान व्यापक डेटा सेंटर इकोसिस्टम से जुड़े रोजगार को दिखाता है।

डेटा सेंटर रोजगार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके लिए सिर्फ आईटी विशेषज्ञों की जरूरत नहीं होती। डेटा सेंटर के डिजाइन और चलाने के लिए इलेक्ट्रकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर नेटवर्क इंजीनियर क्लाउड इंजीनियर, सर्वर इंजीनियर साईबर स्पेशलिस्ट डेटा सेंटर टेकनिशियन और फेसिलिटी मैनेजर जैसे लोगों की जरूरत होती है। एआई के विस्तार से रोजगार का एक नया वर्ग भी तैयार हो रहा है। आने वाले समय में एआई इंफ्रा इंजिनियर, जीपीयू इंफ्रा स्पेशलिस्ट, ऑटोमेशन इंजीनियर और साइट रिलियबिलिटी इंजीनियर जैसी नौकरियों की मांग बढ़ सकती है।

डेटा सेंटरों में बैंक, कंपनियों, सरकारी संस्थानों और नागरिकों से जुड़ा संवेदनशील डेटा होता है। इसलिए डेटा सेंटर जितने बढ़ेंगे, साइबर सुरक्षा की जरूरत भी उतनी ही बढ़ेगी। संचालन केंद्र विश्लेषक, नेटवर्क सुरक्षा इंजीनियर, क्लाउड सुरक्षा विशेषज्ञ, डेटा सुरक्षा विशेषज्ञ, पहचान एवं पहुंच प्रबंधन विशेषज्ञ और साइबर घटना प्रतिक्रिया विशेषज्ञ जैसे पेशेवरों की मांग भी इससे बढ़ने की संभावना है। डेटा लोकलाइजेशन और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन व्यवस्था के विस्तार के साथ कम्प्लायंस और डेटा गवर्नेंस विशेषज्ञों के लिए भी नया रोजगार बाजार बन सकता है।

8 गीगावाट तक पहुंचने की तैयारी

भारत के डेटा सेंटर क्षेत्र का विस्तार कितना तेज है, इसका अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। वर्ष 2020 में देश में स्थापित डेटा सेंटर की क्षमता लगभग 375 मेगावाट थी। अगस्त 2026 तक यह बढ़कर

करीब 1.57 गीगावाट हो गई है। वर्ष 2030 तक इसके लगभग 8 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में इस क्षेत्र में करीब 70 अरब डॉलर का निवेश पहले से हो रहा है, जबकि लगभग 90 अरब डॉलर की अतिरिक्त परियोजनाओं की घोषणा हो चुकी है। यानी आने वाले वर्षों में केवल डेटा सेंटर की बड़ी इमारतें नहीं बनेंगी, बल्कि इनके आसपास बिजली, फाइबर, सड़क, लॉजिस्टिक्स और दूसरे बुनियादी ढांचे की मांग भी बढ़ेगी। जेफरीज के मुताबिक भारत में किराये पर उपलब्ध डेटा सेंटर क्षमता 2026 में करीब 2,076 मेगावाट रह सकती है जो 2031 तक बढ़कर लगभग 9,576 मेगावाट पहुंच सकती है। यानी पांच वर्षों में क्षमता करीब पांच गुना होने की संभावना है। डेटा सेंटर की मौजूदा क्षमता का इस्तेमाल भी 95 से 97 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इस मांग में बड़ी टेक और क्लाउड कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 60 प्रतिशत है, जबकि बैंक और वित्तीय कंपनियां करीब 15 प्रतिशत मांग पैदा कर रही हैं।

135 अरब डॉलर निवेश का अनुमान

रिसर्च फर्म जेफरीज का अनुमान है कि अगले पांच साल में भारत में डेटा सेंटर और सर्वर से जुड़े ढांचे पर करीब 135 अरब डॉलर यानी 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश हो सकते हैं। इसमें लगभग 45 अरब डॉलर डेटा सेंटर बनाने और करीब 90 अरब डॉलर सर्वर तथा दूसरे आईटी उपकरणों पर खर्च हो सकते हैं। 2027 से 2031 के बीच करीब 7,500 मेगावाट नई क्षमता तैयार करने के लिए प्रस्तावित 45 अरब डॉलर में लगभग 16 अरब डॉलर बिजली और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, 11 अरब डॉलर जमीन और भवन, 9 अरब डॉलर रैक और फिटआउट, 7 अरब डॉलर कूलिंग तथा करीब 2 अरब डॉलर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो सकते हैं। यह खर्च ट्रांसफॉर्मर, केबल, स्विचगियर, बैटरी, जनरेटर, चिलर, रैक और फाइबर बनाने वाले उद्योगों को भी बड़ा बाजार दे सकता है। डेटा सेंटर में बिजली कभी बंद नहीं होती है। इसलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम इस उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में है। इलेक्ट्रिकल कंपनियों को भी इससे बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। डेटा सेंटर के ऑर्डर मिलने से इन कंपनियों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

9.3 अरब डॉलर का किराया बाजार

डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ने का सीधा असर इनके किराये के बाजार पर भी पड़ेगा। जेफरीज के मुताबिक, भारत में डेटा सेंटर

डेटा सेंटर है क्या?

सरल भाषा में डेटा सेंटर एक सुरक्षित डिजिटल परिसर है जहां सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्किंग उपकरण, बिजली व्यवस्था, कूलिंग सिस्टम और सुरक्षा उपकरण एक साथ काम करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मोबाइल में मौजूद बैंकिंग ऐप पर अपना बैलेंस देखने के लिए क्लिक किया। उसकी रिक्वेस्ट इंटरनेट के जरिए डेटा सेंटर तक पहुंचती है। सबसे पहले सिक्योरिटी लेयर जांच होती है कि अनुरोध सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद लोड बैलेंसर उस रिक्वेस्ट को उपलब्ध सर्वर तक पहुंचाता है ताकि किसी एक सर्वर पर ज्यादा दबाव न पड़े। एप्लिकेशन सर्वर यह समझता है कि ग्राहक को कौन सी जानकारी चाहिए। जरूरत पड़ने पर एपीआई दूसरी एप्लिकेशन से संपर्क करता है। फिर डेटाबेस सर्वर संबंधित जानकारी खोजता है और उसे वापस एप्लिकेशन सर्वर को भेज देता है। इसके बाद जवाब नेटवर्क के रास्ते वापस ग्राहक के मोबाइल तक पहुंचता है। यह पूरी प्रक्रिया कई मामलों में केवल एक से दो सेकंड में पूरी हो सकती है। यही प्रक्रिया अलग-अलग रूप में यूपीआई, ई-कॉमर्स, सरकारी पोर्टल, क्लाउड, वीडियो स्ट्रीमिंग और एआई सेवाओं के पीछे लगातार चलती रहती है।

डेटा सेंटर का संचालन किसी सामान्य कार्यालय की तरह नहीं होता। इसे लगातार चलना पड़ता है। कुछ सेकंड के लिए बिजली बंद होने पर भी बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाएं और दूसरी डिजिटल गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इसीलिए डेटा सेंटर में सामान्य बिजली के साथ यूपीएस और बैकअप जनरेटर लगाए जाते हैं। बिजली वितरण के लिए अलग से मजबूत सिस्टम तैयार किया जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती गर्मी है। हजारों सर्वर लगातार काम करते हैं और बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करते हैं। इस गर्मी को नियंत्रित करने के लिए एचवीएसी सिस्टम, एडवांस एयरफ्लो मैनेजमेंट और लिक्यूड कूलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एआई डेटा सेंटर के विस्तार से डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग, एडिवेटिक कूलिंग, इमरशन कूलिंग और क्लोज लूप लिक्विड कूलिंग जैसी तकनीकों की अहमियत बढ़ रही है।

आने वाले वर्षों में केवल डेटा सेंटर की बड़ी इमारतें नहीं बनेंगी, बल्कि इनके आसपास बिजली, फाइबर, सड़क, लॉजिस्टिक्स और दूसरे बुनियादी ढांचे की मांग भी बढ़ेगी।

रेंटल मार्केट 2026 में करीब 2 अरब डॉलर से बढ़कर 2031 में लगभग 9.3 अरब डॉलर का हो सकता है। यानी पांच वर्षों में बाजार चार गुना से अधिक हो सकता है। मुंबई और चेन्नई अभी देश के प्रमुख डेटा सेंटर केंद्र हैं। दोनों शहरों को समुद्र के नीचे बिछी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट केबल तक आसान पहुंच का लाभ मिलता है। लेकिन 5जी, एज कम्प्यूटिंग और क्षेत्रीय डिजिटल सेवाओं के विस्तार से आने वाले वर्षों में टियर-2 शहरों में भी छोटे और मध्यम डेटा सेंटर तैयार हो सकते हैं। इससे तकनीकी नौकरियां महानगरों से बाहर जाएंगी और स्थानीय स्तर पर बिजली, फाइबर, परिवहन, होटल, सुरक्षा, आवास और रिटेल की मांग बढ़ सकती है।

डेटा सेंटर जितने बढ़ेंगे, बिजली की मांग भी उतनी ही बढ़ेगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार इस क्षेत्र की बिजली मांग 2031-32 तक करीब 17 गीगावाट पहुंच सकती है। इसीलिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और सोलर पार्क जैसी योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में डेटा सेंटरों को इन्फ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट में शामिल किया था। इसका मतलब है कि इन्हें सड़क, हवाई अड्डे और बिजली ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की श्रेणी में वित्त उपलब्ध कराने में आसानी हो सकती है। 2026-27 के बजट में पात्र विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए भारत स्थित डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे का प्रावधान भी किया गया है।

सेमीकंडक्टर और एआई मिशन से भी मिलेगी ताकत

डेटा सेंटर के विस्तार को सरकारी योजनाओं से भी समर्थन मिल रहा है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 2.0 के लिए 1,27,500 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। जबकि इंडिया एआई मिशन के लिए 10,371.92 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का आवंटन 22,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया गया है। आईटी हार्डवेयर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना 2.0 का उद्देश्य सर्वर सहित आईटी हार्डवेयर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इन योजनाओं से डेटा सेंटर के विस्तार में मदद मिल रही है।

2032 तक 17 गीगावाट बिजली की जरूरत

डेटा सेंटर जितने बढ़ेंगे, बिजली की मांग भी उतनी ही बढ़ेगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार इस क्षेत्र की बिजली मांग 2031-32 तक करीब 17 गीगावाट पहुंच सकती है। इसीलिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और सोलर पार्क जैसी योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इससे नवीकरणीय ऊर्जा इंजीनियर, बैटरी भंडारण विशेषज्ञ, ऊर्जा प्रबंधक, सतत विकास प्रबंधक, कार्बन लेखांकन विशेषज्ञ और जल दक्षता इंजीनियर जैसे नए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

जेफरीज के अनुसार, भारत में बिजली और डेटा सेंटर तैयार करने की लागत कई दूसरे देशों से कम हो सकती है। औसतन 25 से 40 प्रतिशत तक लागत लाभ मिलने की संभावना भारत को वैश्विक डेटा सेंटर निवेश के लिए आकर्षक बना सकती है। इसके साथ देश में डेटा रखने की बढ़ती जरूरत, क्लाउड सेवाओं का विस्तार, एआई का तेजी से इस्तेमाल और सरकारी डिजिटल सेवाएं इस क्षेत्र की मांग को लगातार बढ़ा रही हैं। डेटा सेंटर का विस्तार जितना बड़ा अवसर है, उतनी ही बड़ी चुनौती पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। 2030 तक करीब एक लाख कुशल पेशेवरों की मांग होने का अनुमान बताता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कौशल विकास संस्थानों को उद्योग की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम बदलने होंगे। भविष्य के कर्मचारी के लिए केवल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिस्टम जानना पर्याप्त नहीं होगा। उसे मिशन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, ऑटोमेशन, ऊर्जा दक्षता, कूलिंग और डेटा सेंटर संचालन की समझ भी विकसित करनी होगी।■

23+ वर्ष
ई-कॉमर्स के

ई-आश्वासन
भारत

डिजिटल राष्ट्र के लिए
वाणिज्य का नया स्वरूप

एम एस टी सी लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
MSTC Limited
A Government of India Enterprise

CIN : L27320WB1964GOI026211

एमएसटीसी लिमिटेड - कन्ट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबिलिटी

गौरवमय 62 वर्ष

- प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड
- संसाधनों के मुद्रीकरण के लिए पसंदीदा सेवा प्रदाता
- मजबूत नियामक और अनुपालन ढांचा
- विविध क्षेत्र के अनुभव के साथ पूरे भारत में उपस्थिति
- अत्याधुनिक, मजबूत, लगातार बढ़ती प्रौद्योगिकी संरचना



भारत के बी2बी और बी2जी डिजिटल इकोसिस्टम का भरोसेमंद साथी

ई–कॉमर्स सेवाएँ

- ई-नीलामी
- कस्टमाइज्ड नीलामी/सेवाएँ
- ऑनलाइन ड्रॉ प्रणालियाँ
- क्रय सेवाएँ

क्षेत्र

कोयला, इस्पात, लौह अयस्क, विद्युत, विमानन, वन, परिवहन, खनिज, रियल एस्टेट, दूरसंचार, स्क्रैप, ईएलवी

डिजिटल एक्सचेंज

सीपीसीबी

- ईपीआर ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज शुरू होने के लिए तैयार ...
  आगे और भी

एमएसटीसी ट्रैवल पोर्टल

- जल्द आ रहा है
- सीमलेस डिजिटल ट्रैवल पोर्टल
- बी2बी और बी2सी के लिए समेकित समाधान

भविष्य के लिए तैयार डिजिटल पहल

- औद्योगिक और भारी उपकरण की बिक्री और लीजिंग के लिए मार्केटप्लेस

Upkaran
Empowering Growth

खुदरा प्रचालन का डिजिटलीकरण

केंपीकेवी
सहायक ईआरपी

- योजना, क्रय, इन्वेन्ट्री प्रबंधन और पीओएस समाधान
- केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के लिए पोर्टल ...
  आगे और भी

कस्टमाइज्ड एप्लिकेशन का विकास

- डैशबोर्ड
- वेबसाइट और पोर्टल
- लेनदेन का डिजिटलीकरण

एनवाईसीएस की एआरजीबीएम

सहकारी क्षेत्र में युवाओं को अवसर मुहैया कराने पर एनवाईसीएस का फोकस

युवा सहकार टीम



- एनवाईसीएस की 25वीं वार्षिक प्रतिनिधि सामान्य निकाय बैठक हुई सम्पन्न
- युवा शक्ति, सहकारिता और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने का लिया गया साझा संकल्प

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) का फोकस सहकारिता के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने, युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करने और सहकारी क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसरों को बढ़ावा देने पर है। एनवाईसीएस का मानना है कि युवा केवल देश का भविष्य ही नहीं, बल्कि वर्तमान विकास यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार भी हैं। उनकी ऊर्जा, विचारशीलता, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक सोच को सहकारिता के सिद्धांतों के साथ जोड़कर समाज और राष्ट्र के विकास को नई दिशा दी जा सकती है। युवाओं की इस सहकारी संस्था की 12 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 25वीं वार्षिक प्रतिनिधि सामान्य निकाय बैठक (एआरजीबीएम) में युवा शक्ति, सहकारिता और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने का साझा संकल्प लिया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों, निदेशक मंडल तथा देशभर से आए जिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।

यह आयोजन युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को और अधिक सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा। देशभर से आए जिला प्रतिनिधियों तथा निदेशक मंडल के सदस्यों ने बैठक में अपने अनुभव, विचार एवं सुझाव साझा किए। प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता ने बैठक को सार्थक एवं प्रभावी बनाया। एनवाईसीएस के निदेशक मंडल ने इस दौरान जिला प्रतिनिधियों को वर्षभर के कार्यों, वित्तीय स्थिति एवं उपलब्धियों से अवगत कराया। साथ ही, आगामी वर्ष की योजनाओं पर चर्चा की गई तथा आवश्यक विषयों पर जिला प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। जिला प्रतिनिधियों ने उपरोक्त विषयों पर सहमति दी।



एनवाईसीएस के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र साहू ने उपस्थित जिला प्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हुए संगठन के प्रति उनके समर्पण, सक्रिय सहभागिता और सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती में प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके नेतृत्व, अनुभव एवं सामूहिक प्रयासों के माध्यम से संस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को संगठन के प्रभावी एवं बेहतर नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

एनवाईसीएस के प्रबंधन समिति के चेयरमैन श्री राजेश पांडे ने उपस्थित जिला प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें भविष्य में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने, नए विचारों एवं पहलों के साथ संगठन को आगे बढ़ाने और युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक प्रयास एनवाईसीएस की आगामी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

एआरजीबीएम में एनवाईसीएस के आय-व्यय, वित्तीय स्थिति तथा अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय विषयों से संबंधित जानकारी प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत की गई। एनवाईसीएस की माइक्रोफाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट एवं बजट भी बैठक में पेश की गई। प्रतिनिधियों को बताया गया कि संस्था मुनाफे में है। इससे संस्था के वित्तीय कामकाज में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों की भूमिका को सशक्त बनाने और उनकी नेतृत्व क्षमता के विकास के साथ-साथ सहकारिता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने, उनकी सहभागिता बढ़ाने तथा सहकारी क्षेत्र को आधुनिक सोच और तकनीक के साथ आगे ले जाने की भावना को प्रमुखता दी गई। देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधियों के अनुभवों और दृष्टिकोणों ने संस्था के कार्यों को व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया तथा भविष्य की दिशा को लेकर सामूहिक सोच को और मजबूत किया।

निदेशक मंडल द्वारा यह दोहराया गया कि संस्था का संकल्प है कि आने वाले समय में भी युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करने, सहकारिता की भावना को जन-जन तक पहुंचाने और युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही युवाओं की रचनात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देते हुए उन्हें राष्ट्र की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए नए अवसरों और पहलों को आगे बढ़ाया जाएगा। युवा शक्ति और सहकारिता की सामूहिक ऊर्जा के साथ एनवाईसीएस एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। 25वीं एआरजीबीएम ने सामूहिक सहभागिता, युवा नेतृत्व और सहकारिता की भावना के माध्यम से विकास को नई गति देने के संकल्प को और मजबूत किया। यह सभा केवल वार्षिक गतिविधियों की समीक्षा का अवसर नहीं रही, बल्कि युवाओं की सहभागिता, नेतृत्व विकास और सहकारिता के माध्यम से सामूहिक प्रगति की दिशा में नए संकल्प लेने का महत्वपूर्ण मंच भी बनी। प्रतिनिधियों के विचारों और अनुभवों ने संगठन की आगामी कार्ययोजना को नई दिशा प्रदान की।■

युवा केवल देश का भविष्य ही नहीं, बल्कि वर्तमान विकास यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार भी हैं। उनकी ऊर्जा, विचारशीलता, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक सोच को सहकारिता के सिद्धांतों के साथ जोड़कर समाज और राष्ट्र के विकास को नई दिशा दी जा सकती है।



एनवाईसीएस की केरल क्षेत्रीय बैठक का आयोजन

युवा सहकार टीम

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) की केरल क्षेत्रीय बैठक का सफल आयोजन 25 सितंबर, 2026 को किया गया। इस बैठक में एनवाईसीएस एवं सहकार भारती के राष्ट्रीय एवं वरिष्ठ नेतृत्व के साथ-साथ केरल की विभिन्न शाखाओं के अध्यक्षों, सचिवों और प्रबंधन समिति के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य शाखा स्तर पर कार्य कर रहे पदाधिकारियों के साथ सीधे संवाद करना, उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को समझना तथा वर्तमान समय में सहकारी संस्थाओं के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा करना था। इस दौरान एनवाईसीएस और उसकी शाखाओं के भविष्य के विकास के लिए आवश्यक दिशा और कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर एनवाईसीएस के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र साहू, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री राजेश बाबूलाल पांडे, संस्थापक अध्यक्ष और कझाकूट्टम (केरल) के विधायक श्री वी. मुरलीधरन, सीईओ डॉ. रामचंद्र कुलकर्णी और सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संजय पाचपोर की गरिमामयी उपस्थिति रही। क्षेत्रीय बैठक को एक ऐसे मंच के रूप में आयोजित किया गया, जहां शाखाओं के प्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं, अनुभवों और सुझावों को सीधे वरिष्ठ नेतृत्व के सामने रखने का अवसर मिला। शाखा अध्यक्षों, सचिवों और प्रबंधन समिति के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं, कामकाज से जुड़ी चुनौतियों और भविष्य में बेहतर कार्य करने के लिए आवश्यक



क्षेत्रीय बैठक में शाखाओं के प्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं, अनुभवों और सुझावों को वरिष्ठ नेतृत्व के सामने रखने का अवसर मिला।

सुझाव साझा किए। संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व ने शाखा प्रतिनिधियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और विभिन्न विषयों पर आवश्यक मार्गदर्शन एवं सुझाव दिए। इस संवाद से राष्ट्रीय नेतृत्व और शाखा स्तर के पदाधिकारियों के बीच आपसी समझ और सहयोग को और मजबूत करने का अवसर मिला।

बैठक में वर्तमान आर्थिक, वित्तीय और तकनीकी परिवेश में सहकारी संस्थाओं के सामने आ रही नई चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। बदलते समय के साथ सहकारी संस्थाओं के लिए अपनी कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना और नई तकनीक को अपनाना महत्वपूर्ण है। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि सहकारी संस्थाओं को आधुनिक तकनीक, बदलती आर्थिक परिस्थितियों, सदस्यों एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के अनुरूप लगातार अपने काम करने के तरीके में सुधार करना होगा। इसके साथ ही सहकारिता के मूल सिद्धांतों, सहयोग, सहभागिता, पारदर्शिता और सामूहिक विकास को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है।

एनवाईसीएस के भविष्य के विकास को लेकर नए अवसरों की पहचान करने और शाखाओं की कार्यक्षमता को और मजबूत करने पर भी बैठक में विचार-विमर्श किया गया। बदलते समय में सहकारी संस्थाओं के लिए नए क्षेत्रों में संभावनाओं को तलाशना, अपनी सेवाओं को बेहतर बनाना और सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार काम करना जरूरी है। इस दिशा में शाखाओं को स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को समझने, नए अवसरों की पहचान करने और संगठन के व्यापक उद्देश्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सामान्य सत्र के बाद विभिन्न शाखाओं के साथ वन-टू-वन बैठकें भी आयोजित की गईं। इन बैठकों में प्रत्येक शाखा को अपनी विशेष समस्याओं, आवश्यकताओं, स्थानीय परिस्थितियों और कामकाज से जुड़े विषयों पर वरिष्ठ प्रबंधन के साथ विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला।

नए अवसर तलाश रहा नेफेड

युवा सहकार टीम

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) ने वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन करते हुए अपने कारोबार को नई दिशा देने की रणनीति तैयार की है। नेफेड की 69वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में फेडरेशन ने न केवल वित्तीय उपलब्धियों की समीक्षा की, बल्कि भविष्य के लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल विकसित करने पर जोर दिया जो सरकारी योजनाओं पर निर्भरता कम करते हुए संगठन को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बना सके।

एजीएम में नेफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल ने कहा कि फेडरेशन का लक्ष्य केवल लाभ बढ़ाना या बेहतर वित्तीय आंकड़े हासिल करना नहीं है, बल्कि संगठन को 'भविष्य के लिए तैयार' बनाना है। नेफेड को अपने गैर-सरकारी कारोबार का विस्तार इस स्तर तक करना होगा कि किसी भी चुनौती की स्थिति में संगठन मजबूती के साथ काम कर सके। नेफेड अब अपनी पारंपरिक भूमिका के साथ-साथ निजी कंपनियों, संस्थागत खरीदारों और व्यावसायिक चैनलों के साथ नए अवसर तलाश रहा है। फेडरेशन का मूल मंत्र 'किसान से किचन तक' की सोच के साथ कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। वित्त वर्ष 2025-26 में नेफेड का कुल कारोबार 29,884.72 करोड़ रुपये रहा, जबकि शुद्ध लाभ 423.14 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। एजीएम में सदस्य फेडरेशनों और सहकारी समितियों के लिए 15 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की गई। सालाना बैठक में देशभर से 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

नेफेड चेयरमैन जेठाभाई अहीर ने एजीएम को संबोधित करते हुए कहा कि फेडरेशन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान



वित्त वर्ष 2025-26 में 29,884 करोड़ रुपये का किया कारोबार, 423 करोड़ रुपये का हुआ मुनाफा

गैर-सरकारी कारोबार बढ़ाने, रिटेल विस्तार और डिजिटल बदलाव पर बढ़ा जोर

के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इनमें मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ)), मूल्य अंतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद एवं भंडारण योजना (पीपीएसएस) शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना और कृषि उत्पादों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है।

दीपक अग्रवाल के अनुसार, नेफेड अब केवल सरकारी खरीद तक सीमित नहीं रहना चाहता। फेडरेशन निजी क्षेत्र, संस्थागत खरीदारों और खुदरा बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। नेफेड का रिटेल कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में जहां रिटेल कारोबार 42 करोड़ रुपये था, वहीं चालू वित्त वर्ष के केवल छह महीनों में यह 48 करोड़ रुपये को पार कर चुका है। मौजूदा रफ्तार जारी रहने पर वर्ष के अंत तक रिटेल कारोबार 100 करोड़ रुपये के स्तर को पार कर सकता है। रिटेल विस्तार के लिए पैक्स, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से 50 नए स्टोर खोलने की योजना बनाई गई है। नेफेड के उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने के लिए रेलवे, एचपीसीएल और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की जा रही है।

नेफेड ने अपने संस्थागत कारोबार को भी मजबूत करना शुरू किया है। फेडरेशन के कई उत्पादों को सीडीएस कैंटीन में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे करीब 1,200 आउटलेट के नेटवर्क तक पहुंच बनाई जा सकेगी। इसके अलावा भारतीय सेना को दालों की आपूर्ति के बाद अब चावल की आपूर्ति भी शुरू की है। साथ ही रेलवे, जिसमें वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं, के लिए खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। नेफेड के प्रीमिक्स चाय, बिस्किट और जूस जैसे उत्पाद आईआरटीसी के माध्यम से रेलवे नेटवर्क तक पहुंच रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी फेडरेशन अपने उत्पादों का विस्तार कर रहा है। यूएई और कनाडा जैसे बाजारों तक पहुंच बनाने की दिशा में नेफेड काम कर रहा है।■

पीएम की सेवा के 25 साल और विकसित भारत का संकल्प





विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संवैधानिक जिम्मेदारी के 25 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक दायित्व की शुरूआत की थी। वह यात्रा आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प तक पहुंची है। इन 25 वर्षों में परिस्थितियां बदलीं, जिम्मेदारियां बढ़ीं, चुनौतियों का स्वरूप बदला, लेकिन एक चीज निरंतर रही जो राष्ट्र और समाज के प्रति उनका सेवा भाव है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को पद और प्रतिष्ठा की यात्रा नहीं, बल्कि सेवा, साधना और राष्ट्र निर्माण की यात्रा बनाया है।

उनके 25 वर्ष का यह सफर केवल एक व्यक्ति की राजनीतिक यात्रा नहीं है। यह बदलते भारत की कहानी है। यह उस नेतृत्व की कहानी है जिसने कठिन परिस्थितियों को अवसर में बदलने का प्रयास किया। चुनौतियों को संकल्प में बदला और शासन को जनसेवा का माध्यम बनाया। मेरे लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के 25 वर्षों को समझने का सबसे महत्वपूर्ण आधार उनका यह भाव है कि सत्ता उनके लिए साध्य नहीं, बल्कि सेवा का साधन है। उन्होंने स्वयं को प्रधानमंत्री से अधिक प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि उनके शासन की प्राथमिकताओं के केंद्र में देश का गरीब, किसान, महिला, युवा, श्रमिक, जनजातीय समाज और समाज का अंतिम व्यक्ति दिखाई देता है।

प्रधानमंत्री जी का विश्वास है कि विकास का वास्तविक लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचे, जो दशकों तक विकास की मुख्यधारा से दूर रहा। इसी सोच का परिणाम है कि जनधन खातों से करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों की माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को जनआंदोलन बनाया। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों के पक्के घर के सपने को साकार करने में अभूतपूर्व काम किया। आयुष्मान भारत ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का नया भरोसा पैदा किया। वहीं किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सीधी आर्थिक

सहायता पहुंचाई गई। इसी तरह, डिजिटल इंडिया ने भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था की शक्ति से जोड़ा। यूपीआई और डिजिटल भुगतान ने दुनिया को भारत की तकनीकी क्षमता का नया उदाहरण दिया।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता योजनाओं को जनभागीदारी के अभियान में बदल देना है। स्वच्छ भारत मिशन इसका उदाहरण है। फिट इंडिया, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, हर घर तिरंगा, आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियानों ने शासन और समाज के बीच भागीदारी का एक नया रिश्ता बनाया है।

महिला सशक्तीकरण को प्रधानमंत्री जी ने केवल कल्याण की दृष्टि से नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की शक्ति के रूप में देखा। करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला, आवास, शौचालय, बैंक खाते और मुद्रा ऋण से जोड़ने के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों और 'लखपति दीदी' जैसे प्रयासों से उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। वहीं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया।

युवा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के केंद्र में रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने युवाओं के भीतर उद्यमिता और नवाचार का विश्वास पैदा किया है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। जबकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान भारत के आर्थिक आत्मविश्वास के प्रतीक बने हैं।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में भी अभूतपूर्व गति दिख रही है। सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाएं, एक्सप्रेसवे और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी ऐसे भारत की तस्वीर पेश करते हैं जो भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए अपने बुनियादी ढांचे को तैयार कर रहा है। उनके नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी आवाज को और भी अधिक मजबूती से रखा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका आज पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली दिखाई देती है। ब्रिक्स और जी20 की भारत की अध्यक्षता ने 'वसुधैव कुटुंबकम्'की भावना के साथ भारत की वैश्विक दृष्टि को सामने रखा।

प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व केवल बड़े फैसलों तक सीमित नहीं है। उनकी कार्यशैली की एक बड़ी विशेषता यह है कि जनहित के विषय को भी राष्ट्र निर्माण से जोड़ते हैं। जनजातीय समाज के विकास और सम्मान को उन्होंने विशेष प्राथमिकता दी है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हो या जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कनेक्टिविटी और आजीविका के अवसरों का विस्तार, इन कदमों से जनजातीय समाज को विकास का सहभागी बनाने की भावना स्पष्ट दिखाई देती है।

आज भारत आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है। दुनिया भारत को अब केवल बड़े बाजार के रूप में नहीं देखती है। एक विश्वसनीय साझेदार, उभरती आर्थिक शक्ति और वैश्विक चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भी देख रही है। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, डिजिटल क्षमता, युवा शक्ति, वैज्ञानिक उपलब्धियां और वैश्विक कूटनीति इस परिवर्तन की कहानी कह रही हैं। इन उपलब्धियों के बीच उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने का विराट लक्ष्य रखा है। यह ऐसा भारत बनाने का संकल्प है जो आत्मनिर्भर हो, आधुनिक हो, समावेशी हो, सुरक्षित हो, तकनीकी रूप से सक्षम हो और अपनी संस्कृति तथा विरासत पर गर्व करने वाला हो।

छत्तीसगढ़ के लिए भी यह संकल्प उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि मजबूत छत्तीसगढ़ ही मजबूत विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा।■

युवा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के केंद्र में रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने युवाओं के भीतर उद्यमिता और नवाचार का विश्वास पैदा किया है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है।

शी मार्ट की शुरुआत, सशक्त होंगी महिलाएं



एनसीसीएफ के 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट के साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में खुलेंगे 300 से अधिक 'शी मार्ट'

महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिला उद्यमियों को बाजार से सीधे जोड़ने का प्रयास है शी मार्ट

प्रोक्योरमेंट से लेकर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और सीधे रिटेल मार्केट तक पहुंच, किसानों और महिला उद्यमियों को मिलेगा लाभ

युवा सहकार टीम

सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण और गरीब महिलाओं को सशक्त बनाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। महिला उद्यमिता और ग्रामीण उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) के माध्यम से दक्षिण भारत में सहकारी रिटेल नेटवर्क के विस्तार की पहल की है। केरल के कोल्लम में 'वनितम शी-मार्ट' स्टोर्स की शुरुआत के साथ एनसीसीएफ ने अपने 'जनः' ब्रांड के उत्पादों की बिक्री भी शुरू की है। इस मॉडल को केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक स्टोर्स तक विस्तार देने की योजना है। सहकारी क्षेत्र में 'शी मार्ट' की जिस पहल की शुरुआत हुई है, उसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले केरलम से हुई है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण महिला उद्यमियों, सहकारी संस्थाओं और छोटे उत्पादकों को संगठित रिटेल बाजार से जोड़ना है। इसके जरिये स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को बिक्री का स्थायी प्लेटफॉर्म मिलने के साथ पैकेजिंग, ब्रांडिंग, वितरण और खुदरा कारोबार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कोल्लम में महिला सशक्तीकरण और सहकारिता से जुड़ी विभिन्न पहलों का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री का मूल उद्देश्य सहकारिता से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। एनसीसीएफ की इस नायाब पहल से महिला सशक्तीकरण को बल मिलेगा और महिलाएं सशक्त होंगी।

एनसीसीएफ की इस पहल का प्रमुख उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना है। इसी के साथ किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य दिलाना भी इसका लक्ष्य है, जिससे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य भी मिल सके। नेफेड की मोबाइल वैन के माध्यम से प्याज, भारत ब्रांड आटा और भारत ब्रांड चावल किसानों और आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने की पहल भी केरलम में हुई है। दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहन मिशन के तहत महिला किसानों को उड़द और चने के बीजों के किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी प्रकार नेफेड

कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग दो हजार परिवारों की बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने का कार्य भी किया गया है। इससे महिला सशक्तीकरण को बल मिलेगा।

इस अवसर पर एनसीसीएफ और द सेंट्रल फाइनेंशियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट को-ऑपरेटिव (इंडिया) लिमिटेड (उक्ऋउकउक) के बीच समझौता भी किया गया। इसके साथ ही एनसीसीएफ के 'जनः' ब्रांड के साथ भारतीय मत्स्य प्रवर्तक संघम के मत्स्य उत्पादों के सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन के लिए और एनसीसीएफ और भारत लझना सहकारी समिति के बीच केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक में 300 शी मार्ट शॉप्स खोलने के लिए भी समझौता किया गया।

महिला उद्यमिता को नई पहचान दे रहे 'शी मार्ट'

शी मार्ट विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित और उनके स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट्स (दुकानें) हैं जिन्हें स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और क्लस्टर-स्तरीय संघों के माध्यम से स्थापित और प्रबंधित किया जा रहा है। ये मार्ट न केवल ग्रामीण उत्पादों को एक संगठित पहचान दे रहे हैं, बल्कि महिलाओं को बिचौलियों के बिना सीधे ग्राहकों से जुड़ने का मौका भी दे रहे हैं। महिलाओं को घरेलू स्तर पर छोटे काम करने की बजाय व्यावसायिक स्टोर चलाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026 में 'स्वयं सहायता उद्यमी मार्ट' (शी मार्ट) योजना की घोषणा की। यह पहल ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपनी खुद की दुकानें चलाने और बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद कर रही है।

शी मार्ट के जरिए भारत सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को अब एक 'लेबर' के रूप में नहीं, बल्कि एक 'लीडर' के रूप में पहचान दे रही है। यह योजना देश के ग्रामीण बाजारों के स्वरूप को पूरी तरह बदलने और करोड़ों महिलाओं को वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सामर्थ्य रखती



है। इन माट्र्स के जरिए महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, कपड़े और खाद्य पदार्थ जैसे उत्पाद बड़े शहरों और राष्ट्रीय स्तर के बाजारों तक पहुंच सकेंगे। इनमें महिलाओं को इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक ट्रैकिंग और डिजिटल बिलिंग जैसे आधुनिक व्यावसायिक गुर सिखाए जाएंगे।

महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए 'शी मार्ट' के महत्व को रेखांकित करते हुए अमित शाह ने कहा कि शी मार्ट की अवधारणा महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिला उद्यमियों को बाजार और उपभोक्ताओं से सीधे जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। इस तरह की योजनाओं से नेफेड, केंद्रीय भंडार और अमूल जैसे सहकारी संस्थानों के माध्यम से महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को व्यापक स्तर पर विस्तार देने में सहायता मिलेगी। शी मार्ट के विस्तार और इससे किसानों तथा महिला उद्यमियों के लिए बनने वाले नए अवसरों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक शी मार्ट स्टोर स्थापित करने की योजना है, जहां भारत ब्रांड के साथ-साथ स्थानीय उत्पाद भी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। इसके माध्यम से उत्पादों की खरीद, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और सीधे रिटेल मार्केट तक पहुंच बनाना है। इन सभी स्तरों पर किसानों और महिला उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा।■

शी मार्ट विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित और उनके स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट्स (दुकानें) हैं जिन्हें स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और क्लस्टर-स्तरीय संघों के माध्यम से स्थापित और प्रबंधित किया जा रहा है। ये मार्ट न केवल ग्रामीण उत्पादों को एक संगठित पहचान दे रहे हैं, बल्कि महिलाओं को बिचौलियों के बिना सीधे ग्राहकों से जुड़ने का मौका भी दे रहे हैं।

सरस डेयरी के विस्तार से

राजस्थान की डेयरी कोऑपरेटिव को मिलेगी नई रफ्तार



अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट का केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया शिलान्यास

3 लाख लीटर रोजाना होगी दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता जिसे बाद में बढ़ाकर 5 लाख लीटर किया जाएगा

नए प्लांट पर 200 करोड़ रुपये की आएगी लागत, आधुनिक डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा

युवा सहकार टीम

राजस्थान में सहकारी डेयरी आंदोलन अब विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। लगभग पांच दशक से पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा अलवर जिला स्थित सरस डेयरी अब आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अलवर में लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास किया। इसकी शुरुआती दूध प्रसंस्करण क्षमता तीन लाख लीटर रोजाना होगी जिसे बाद में बढ़ाकर पांच लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना है। यह केवल नया प्लांट बनाने की परियोजना नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जिसमें पशुपालक परिवारों के लिए नियमित नकद आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। सरस डेयरी की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ने से अधिक दूध स्थानीय सहकारी व्यवस्था के माध्यम से लिया जाएगा और मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पाद तैयार करने की गुंजाइश भी बढ़ेगी।

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसी पहलू को रेखांकित करते हुए कहा कि सहकारी डेयरी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है। सरस डेयरी के नए प्लांट की क्षमता भविष्य में पांच लाख लीटर रोजाना तक पहुंचने पर बड़ी संख्या में पशुपालकों से दूध की खरीद हो सकेगी। उन्होंने राजस्थान में दुग्ध उत्पादकों को दूध का भुगतान सात दिनों के भीतर दिलाने की व्यवस्था विकसित करने का भी भरोसा दिलाया। इस कार्यक्रम में अलवर के अलावा भीलवाड़ा, जयपुर, पाली और राजसमंद में सरस डेयरी से जुड़ी चार परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं जिनकी कुल लागत 274 करोड़ रुपये है। इनमें डेयरी प्रसंस्करण तथा संबंधित आधारभूत ढांचे की परियोजनाएं शामिल हैं।

दूध से आगे वैल्यू एडिशन की संभावना

सरस डेयरी के आधुनिक डेयरी प्लांट का महत्व केवल कच्चे दूध को पैक करने तक सीमित नहीं रहेगा। ज्यादा प्रसंस्करण क्षमता से दही, छाछ, पनीर, घी और दूसरे मूल्य संवर्धित उत्पादों के उत्पादन की संभावना भी बढ़ेगी है। यही वह क्षेत्र है जहां दुग्ध सहकारिता को केवल दूध खरीदने वाली संस्था से आगे बढ़ाकर ग्रामीण खाद्य अर्थव्यवस्था के बड़े उद्यम में बदला जा सकता है।

नई तकनीक से दूध की गुणवत्ता जांच, शीत श्रृंखला, पैकेजिंग, ऊर्जा दक्षता और प्रसंस्करण को अधिक संगठित किया जा सकता है। इससे बाजार में उत्पाद की शेल्फ

लाइफ और गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता मिलती है। हालांकि इसका वास्तविक आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि संयंत्र की क्षमता का कितना उपयोग होता है, गांवों से दूध संकलन नेटवर्क कितनी तेजी से बढ़ता है और पशुपालकों को खरीद मूल्य तथा भुगतान कितनी नियमितता से मिलता है।

समय पर भुगतान

डेयरी सहकारिता में उत्पादन क्षमता जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण भुगतान चक्र है। छोटे पशुपालक के लिए पशु आहार, चारा, पशु चिकित्सा और घरेलू खर्च लगातार चलते रहते हैं। इसलिए दूध बेचने के बाद मिलने वाली राशि में लंबा अंतर उसकी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में सात दिनों के भीतर भुगतान का लक्ष्य महत्वपूर्ण है। यदि यह व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू होती है तो छोटे पशुपालकों के लिए दूध अपेक्षाकृत नियमित नकदी प्रवाह का स्रोत बन सकता है। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान के दुग्ध उत्पादकों को सरस डेयरी के माध्यम से सात दिन में दूध का मूल्य दिलाने की दिशा में काम किया जाएगा। डेयरी अर्थव्यवस्था का एक सामाजिक पक्ष भी है। ग्रामीण परिवारों में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में महिलाओं की भूमिका व्यापक है। गुजरात के सहकारी डेयरी मॉडल का उल्लेख करते हुए शाह ने महिला दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी को ग्रामीण आर्थिक सशक्तीकरण से जोड़ा।

हर गांव तक कोऑपरेटिव पहुंचाने की तैयार

अमित शाह ने डेयरी के साथ कोऑपरेटिव के नेटवर्क विस्तार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसा ढांचा तैयार करना है जिसमें राजस्थान का कोई गांव सहकारी व्यवस्था से बाहर न रहे। आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 44 हजार सहकारी समितियां हैं। इसी कार्यक्रम में फलोदी, बालोतरा, डीडवाना-कुचामन और प्रतापगढ़ में चार जिला सहकारी बैंकों की शुरुआत भी की



गई। यह विस्तार केवल संस्थाओं की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर कृषि ऋण, भंडारण, डेयरी, इनपुट खरीद और ग्रामीण विपणन तक दिखाई देगा। सहकारी बैंक किसानों को फाइनेंस से जोड़ते हैं जबकि दुग्ध समितियां नियमित बाजार उपलब्ध करा सकती हैं। गोदाम और प्रसंस्करण इकाइयां उत्पादन को बाजार योग्य उत्पाद में बदलने की क्षमता बढ़ाती हैं।

सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास सहकारी डेयरी के लिए महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार है। लेकिन इसकी असली सफलता भवन और मशीनरी से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि इससे कितने नए पशुपालक औपचारिक दुग्ध नेटवर्क से जुड़ते हैं, दूध संग्रह कितना बढ़ता है, किसानों को भुगतान कितनी तेजी से मिलता है और मूल्य संवर्धित उत्पादों से होने वाली अतिरिक्त आमदनी का लाभ उत्पादकों तक किस हद तक पहुंचता है। यदि नया प्लांट पर्याप्त दूध संग्रह, आधुनिक शीत श्रृंखला, बेहतर पशु नस्ल, गुणवत्ता नियंत्रण और समयबद्ध भुगतान से जुड़ता है तो यह दिखाने वाला मॉडल बन सकता है कि बड़े आधुनिक प्लांट और गांव की छोटी दुग्ध समिति को एक ही आर्थिक श्रृंखला में जोड़कर ग्रामीण आय के लिए नए अवसर कैसे तैयार किए जा सकते हैं।■

सरस डेयरी के आधुनिक डेयरी प्लांट का महत्व केवल कच्चे दूध को पैक करने तक सीमित नहीं रहेगा। ज्यादा प्रसंस्करण क्षमता से दही, छाछ, पनीर, घी और दूसरे मूल्य संवर्धित उत्पादों के उत्पादन की संभावना भी बढ़ेगी है। यही वह क्षेत्र है जहां दुग्ध सहकारिता को केवल दूध खरीदने वाली संस्था से आगे बढ़ाकर ग्रामीण खाद्य अर्थव्यवस्था के बड़े उद्यम में बदला जा सकता है।

बस्तर से सहकारिता की नई इबारत



गांवों की समृद्धि पर जोर, पैक्स के विस्तार, जनजातीय सहकारी संस्थाओं को बाजार से जोड़ने और डिजिटल बैंकिंग पर हुआ मंथन

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर नक्सलवाद की समाप्ति के बाद बस्तर में पहली बार आयोजित हुई राष्ट्रीय सहकारी समीक्षा कार्यशाला

युवा सहकार टीम

किसानों को उपज का बेहतर मूल्य, सहकारी संस्थाओं को व्यापक बाजार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लक्ष्य के साथ बस्तर में सहकारिता के भविष्य की रणनीति तैयार की गई। बस्तर की पहचान उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, वन संपदा और ग्रामीण जीवन से है। लंबे समय तक नक्सलवाद की चुनौती झेल चुके इस क्षेत्र में शांति और विकास के साथ स्थानीय आजीविका के अवसर बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सहकारिता किसानों, वनांचल के उत्पादकों और छोटे कारोबारियों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन सकती है। इसी व्यापक उद्देश्य के साथ बस्तर में आयोजित नौवीं राष्ट्रीय सहकारी समीक्षा कार्यशाला में सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने और उनके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने पर मंथन हुआ।

बस्तर से नक्सलवाद की समाप्ति के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर 8 और 9 अक्टूबर को 'सहकार से समृद्धि–आगे की राहः सहकारिता रूपांतरण से व्यापक प्रभाव की ओर' विषय पर आयोजित कार्यशाला में पैक्स, सहकारी बैंकिंग, डेयरी, डिजिटलीकरण, व्यवसाय विविधीकरण और अन्न भंडारण से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। कार्यशाला में शामिल विभिन्न राज्यों के अधिकारियों तथा सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के चर्चा के केंद्र में सहकारिता से जुड़े सुधारों को कागजों से निकाल कर गांवों तक पहुंचाना और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप आर्थिक अवसर विकसित करना था।

बस्तर की जरूरतों से जुड़े सहकारी मॉडल

केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने इस कार्यशाला में राज्यों से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्ययोजना बनाने, जिम्मेदारियां तय करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य की जरूरतें

अलग हैं, इसलिए सफल स्थानीय प्रयोगों को पहचानकर दूसरे क्षेत्रों में भी अपनाने की जरूरत है। बस्तर जैसे वनांचल में इस दृष्टिकोण का महत्व और बढ़ जाता है। यहां सहकारी संस्थाओं को किसानों और स्थानीय उत्पादकों की उपज के एकत्रीकरण, बेहतर विपणन और व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। कार्यशाला में जनजातीय सहकारी संस्थाओं को राज्य और राष्ट्रीय सहकारी संघों से जोड़ने पर भी जोर दिया गया, ताकि स्थानीय उत्पादकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।

पैक्स के विस्तार और आधुनिकीकरण पर जोर

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को केवल ऋण वितरण तक सीमित रखने की बजाय बहुउद्देशीय और आर्थिक रूप से सक्षम संस्थाओं के रूप में विकसित करने पर केंद्र सरकार का फोकस है। इसे लेकर कानून में भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। डॉ. भूटानी ने अगले दो से तीन वर्षों में लगभग 95,000 नई पैक्स के गठन के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए सदस्यता विस्तार और नई समितियों के गठन में तेजी लाने की जरूरत बताई। पैक्स का कम्प्यूटरीकरण भी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। राज्यों को इसका पहला चरण दिसंबर 2026 तक पूरा करने और वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के ऑडिट अक्टूबर 2026 तक संपन्न करने को कहा गया। आधुनिक तकनीक और पारदर्शी लेखा व्यवस्था से सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

किसानों को बाजार से जोड़ेंगी सहकारी संस्थाएं

किसानों और उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसल) की भूमिका पर समीक्षा बैठक में चर्चा हुई। इन संस्थाओं के माध्यम से कृषि उपज के एकत्रीकरण, जैविक उत्पादों, बीज और निर्यात के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं के लिए नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं। इस दौरान सहकारी उत्पादों की बिक्री के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) ने इस पहल में सहयोग की पेशकश की है। डेयरी क्षेत्र में गांवों की अनौपचारिक दुग्ध संग्रहण व्यवस्थाओं को संगठित सहकारी ढांचे से जोड़ने पर भी जोर दिया गया, ताकि दुग्ध उत्पादकों को बेहतर अवसर मिल सकें।■

डिजिटल बैंकिंग से अन्न भंडारण तक

सहकारी बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए साइबर सुरक्षा, आधुनिक कोर बैंकिंग समाधान और इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को जरूरी बताया गया। नाबार्ड द्वारा एकरूप कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने की पहल से तकनीकी कमियों को दूर करने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही बैंकों की स्वायत्तता के साथ जवाबदेही और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण अवसंरचना के विस्तार पर भी मंथन हुआ। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदामों के निर्माण में तेजी लाने का आह्वान किया गया। प्लेज फाइनेंस सहित वैकल्पिक विपणन और वित्तपोषण मॉडलों की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। इन विकल्पों का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था को प्रतिस्थापित करना नहीं, बल्कि उसके अतिरिक्त स्थानीय जरूरतों के अनुरूप टिकाऊ व्यवस्थाएं विकसित करना है। विशेष रूप से गेहूं और धान के अलावा अन्य फसलों के किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए चयनित जिलों में पायलट परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा।

कार्यशाला में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से वित्तीय सहायता, संस्थागत क्षमता निर्माण और राज्यों के सफल प्रयोगों को साझा करने पर भी जोर दिया गया।

बस्तर में आयोजित इस कार्यशाला का महत्व केवल राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता की समीक्षा तक सीमित नहीं है। बस्तर से निकला संदेश स्पष्ट है कि सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए पारदर्शी प्रबंधन, आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। राज्यों की समयबद्ध कार्ययोजनाएं ही इस मंथन को किसानों, उत्पादकों और सहकारी सदस्यों के लिए वास्तविक आर्थिक लाभ में बदल सकेंगी।

केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने इस कार्यशाला में राज्यों से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्ययोजना बनाने, जिम्मेदारियां तय करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य की जरूरतें अलग हैं, इसलिए सफल स्थानीय प्रयोगों को पहचानकर दूसरे क्षेत्रों में भी अपनाने की जरूरत है।

भारत टैक्सी 31 शहरों तक पहुंची



सितंबर में चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू हुई सेवा

10 लाख से अधिक सारथी और 40 लाख से अधिक यात्री इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं

युवा सहकार टीम

सहकारी मॉडल पर शुरू हुई भारत टैक्सी अब चुनिंदा शहरों की सेवा से आगे बढ़कर राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। पिछले महीने चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के पांच शहरों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भारत टैक्सी की सेवा शुरू की गई। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों से होते हुए भारत टैक्सी की शुरुआत देश के 31 शहरों में हो चुकी है। बड़े महानगरों के बाद टियर-2 शहरों में भी सहकारिता आधारित इस टैक्सी सेवा के नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत टैक्सी का लक्ष्य देश के 500 शहरों में अपनी सेवा देने का है।

फरवरी 2026 में औपचारिक शुरुआत के बाद से भारत टैक्सी के प्लेटफॉर्म से 10 लाख से अधिक चालक और करीब 40 लाख यात्री जुड़ चुके हैं। जबकि रोजाना लगभग 20 हजार राइड पूरी हो रही है। सारथियों के खाते में अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंच चुकी है। बड़े महानगरों, पश्चिम भारत और उत्तर भारत के शहरों में लगातार लॉन्च के साथ भारत टैक्सी विस्तार के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है।

यूपी बना विस्तार का बड़ा केंद्र

उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में इसकी सेवा शुरू किए जाने के मौके पर एयरपोर्ट अथॉरिटी, लखनऊ मेट्रो रेल और लखनऊ पुलिस के साथ इसका समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी ताकि यात्रियों को आवागमन और सुरक्षा की सुविधा मिले। भारत टैक्सी शहर के सामान्य आवागमन के साथ एयरपोर्ट और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी यात्राओं में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में लॉन्च केवल एक नए शहर में सेवा शुरू करने तक सीमित नहीं है। भारत टैक्सी की योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों तक पहुंचने की है। यह प्लेटफॉर्म आने वाले समय में महानगरों और टियर-2 से निकलकर छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों तक अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा।

चंडीगढ़ के बाद पंजाब पर नजर

चंडीगढ़ में लॉन्च के साथ भारत टैक्सी ने पंजाब-हरियाणा क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। चंडीगढ़ में लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि आने वाले महीनों में अमृतसर, लुधियाना और जालंधर में भी भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना है।

पूर्व और मध्य भारत में देगी दस्तक

भारत टैक्सी की पहुंच पहले ही दिल्ली-एनसीआर, गुजरात के विभिन्न शहरों, मुंबई, पुणे और जयपुर जैसे बाजारों तक बन चुकी है। अब आगे पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, इंदौर, नागपुर और कोलकाता जैसे शहरों को भी विस्तार की योजना में शामिल किया गया है। भारत टैक्सी की रणनीति साफ है। पहले बड़े शहरों में नेटवर्क तैयार करना, फिर आसपास के टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंच बढ़ाना। भारत टैक्सी का मॉडल पारंपरिक ऐप आधारित कैब कंपनियों से अलग है। यहां सारथी ही मालिक हैं अवधारणा के तहत चालक सहकारी व्यवस्था का हिस्सेदार बनता है और कमीशन आधारित मॉडल की बजाय उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा उसी के पास रहता है।

पहली एजीएम में विस्तार पर फोकस

भारत टैक्सी ने अपनी पहली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अब तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए अगले चरण के विस्तार, परिचालन क्षमता और चालक भागीदारी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की है। एजीएम में सहकारी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों और प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने संस्था के सहकारी परिवहन मॉडल को व्यापक संस्थागत समर्थन का संकेत दिया।

वार्षिक आम बैठक में संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और परिचालन प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष के लिए प्राथमिकताओं, जिम्मेदारियों, लक्ष्यों और कार्ययोजना पर विचार किया गया। संगठन ने अपने अगले विकास चरण में सेवा गुणवत्ता, संचालन दक्षता और चालक सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा है।



भारत टैक्सी का कारोबारी ढांचा पारंपरिक टैक्सी सेवा कंपनियों से अलग चालक-स्वामित्व वाली सहकारी व्यवस्था पर आधारित है। इसका उद्देश्य चालकों को केवल सेवा प्रदाता के बजाय संस्था के आर्थिक हित, स्वामित्व और निर्णय प्रक्रिया से जोड़ना है। यह मॉडल साझा स्वामित्व और सामूहिक भागीदारी के जरिए लंबी अवधि में टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने पर केंद्रित है।

पहली वार्षिक आम बैठक के साथ भारत टैक्सी अब संस्थागत विस्तार के अगले चरण में प्रवेश कर रही है। संस्था के सामने आगे की प्रमुख चुनौती सहकारी ढांचे को बड़े स्तर पर प्रभावी संचालन, बेहतर सेवा और मजबूत चालक भागीदारी में बदलने की होगी। बैठक का समापन साझा स्वामित्व, परिचालन मजबूती और टिकाऊ विकास पर केंद्रित अगले चरण की कार्ययोजना के साथ हुआ।

एजीएम में भारत टैक्सी के चेयरमैन जयेन मेहता, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार बंसल, उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्नल हिमांशु शामिल हुए।■

भारत टैक्सी की योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों तक पहुंचने की है। यह प्लेटफॉर्म आने वाले समय में महानगरों और टियर-2 से निकलकर छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों तक अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा।



20वें एशियाई खेल

तीरंदाजों, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी टीमों ने रखी लाज

सत्येन्द्र पाल सिंह

अमरावती की 17 वर्षीय कुमकुम मोहोद की अगुआई में तीरंदाजों के निशाने पर लगे तीरों से सबसे ज्यादा निकले पांच स्वर्ण पदकों के साथ पुरुष व महिला हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी टीमों ने 20वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत भारत की लाज रखी। ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह की अगुआई में पुरुष और सलीमा टेटे की कप्तानी में महिला हॉकी टीमों ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ सीधे 2028 के लॉस एंजेल्स ओलंपिक के लिए क्वॉलिफाई कर लिया। वहीं श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली पुरुष और हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली महिला क्रिकेट टीम ने अपने-अपने स्वर्ण पदक बरकरार रख एशिया में क्रिकेट में अपनी बादशाहत बरकरार रखी। हरमनप्रीत कौर ने भारत को एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जिताने के बाद क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टी20, वन डे और टेस्ट) की कप्तानी छोड़ दी। अब तीनों फॉर्मेट के स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है।

भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट व हॉकी टीमों की निगाहें अब 2028 के लॉस एंजेल्स ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर लगी हैं। जबकि पुरुष एवं महिला कबड्डी टीमों को यही मलाल है कि इसे अभी तक ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया है। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 49 किलो वजन वर्ग में स्नेच में 87 किलो और जर्क में 111 किलो वजन सहित कुल 198 किलो वजन उठा कर रजत पदक जीता। वहीं प्रणवी उर्स भारत को एशियाई खेलों के इतिहास में महिला गोल्फ में स्वर्ण पदक जिताने वाली पहली गोल्फर बन गईं।

भारत के 495 सदस्यीय दल ने आईची-नगोया (जापान) में आयोजित 20वें एशियाड में 36 खेलों में शिरकत कर 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक के साथ कुल 85 पदक जीते। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। यह भारत का एशियाड के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने हांगजू (चीन) में 2023 के एशियाई खेलों में अपना

पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। यह भारत का एशियाड के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने हांगजू (चीन) में 2023 के एशियाई खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 28 स्वर्ण सहित रिकॉर्ड 106 पदक जीते थे।



सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 28 स्वर्ण सहित रिकॉर्ड 106 पदक जीते थे। भारत के 136 एथलीट 16 खेलों में खाली हाथ लौटे। 2026 एशियाड में पदकों के लिहाज से शीर्ष तीन पर रहे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया भारत से अभी बहुत आगे हैं। भारत की कोशिश एशिया ही नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी खेल ताकत बनने की है। इसके लिए खेलों इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के जरिए जमीनी स्तर पर सार्थक कोशिश जारी है। अच्छी बात यह है कि अभावों के बावजूद ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले खिलाड़ी खेलों में अपना नाम और देश का नाम रोशन करने के जज्बे से मैदान पर ताल ठोक रहे हैं।

20वें एशियाई खेलों में भारत को सेलिंग में एक रजत व दो कांसा सहित तीन पदक, भारोत्तोलन व वू शु में एक-एक रजत, बैडमिंटन, कुराश, मिक्स्ड मार्शल ऑटर्स, रोइंग, सेपक तकरा, सॉफ्ट टेनिस व टेबल टेनिस में एक-एक कांसा मिला। क्रिकेट में पुरुष और महिला टीमों के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बराबर बढ़िया प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के भविष्य की जरूरत को भांप सही वक्त पर सही फैसले लेना है। सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को लेकर किया गया फैसला इसका सटीक उदाहरण है। चीफ कोच शुएर्ड मराइन के मार्गदर्शन में खेली महिला हॉकी टीम ने फाइनल में चीन की दीवार तोड़ 44 बरस बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता। पुरुष हॉकी टीम एशियाई खेलों का स्वर्ण बरकरार रखने में सफल रही। भारत ने फाइनल में मलेशिया पर 5-1 की आसान जीत दर्ज कर 2028 ओलंपिक के लिए क्वॉलिफाई कर लिया। पुरुष हॉकी टीम के चीफ कोच क्रेग फुल्टन ने साफ कर दिया है कि उनका ध्यान ओलंपिक के लिए नई टीम बनाने पर है। फुल्टन

पदक तालिका में शीर्ष पर रही पांच टीमें

स्थान	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	चीन	169	89	83	341
2	जापान	83	95	91	269
3	द.कोरिया	39	43	68	150
4	भारत	21	27	37	85
5	उज्बेकिस्तान	21	25	24	70

के बयान से साफ है कि मनप्रीत सिंह (34 वर्ष), अमित रोहिदास (33 वर्ष), मंदीप सिंह (31 वर्ष), सुमित (29 वर्ष), जर्मनप्रीत सिंह (30 वर्ष) और गोलरक्षक सूरज करकेरा (30 वर्ष) जैसे खिलाड़ियों की जगह भारत की 2028 ओलंपिक टीम में जगह पक्की नहीं है।

तीरंदाज कुमकुम मोहोद की अगुआई में तीरंदाजों ने अपने तीरों से लक्ष्य भेद 2023 में हांगजू की तरह 2026 एशियाई खेलों में भी पांच स्वर्ण सहित कुल नौ पदक जीते। चार भारतीय खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में सबसे ज्यादा तीन तीन पदक जीते। निशानेबाज नीरु ढांडा व तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने दो-दो स्वर्ण व एक-एक रजत जीते। वहीं, धाविका वित्या रामराज ने एक स्वर्ण, एक रजत व एक कांसा जीता। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने दो रजत व एक कांसा जीत इसे यादगार बना दिया। टॉप्स स्कीम के तहत तीरंदाज कुमकुम मोहद को मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण जिताने वाले साहिल जाधव को मात्र 50-50 हजार रुपये और निशानेबाज नीरू ढांडा को एक लाख रुपये की मदद मिली।

वित्या रामराज ने महिलाओं की 4ग्400 मीटर रिले में स्वर्ण, 4ग्400 मिक्स्ड रिले में रजत और 400 मीटर बाधा दौड़ में पीटी ऊषा के 42 बरस पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ कांसा जीत खुद को देश की सर्वश्रेष्ठ धाविका के रूप में स्थापित किया। कुमकुम मोहद, नीरू ढांडा और वित्या रामराज तीनों ने बहुत गरीबी परिवेश से आकर दिखाया कि हौसले बुलंद हों तो सुनहरी कामयाबी मुमकिन है। कुमकुम ने रिकर्व में दक्षिण कोरिया की ओह यिजिन को हरा स्वर्ण जीता। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वीनम, चिकिता तनिपारती, प्रतिका प्रदीप, साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम, कुशाल दलाल, अंकिता भक्त, कीर्ति शर्मा और धीरज बॉम्बादेवरा ने भारत को टीम स्पर्धा में पदक दिलाए।

निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप वैयक्तिक में एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए इस स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली निशानेबाज बनने के साथ कयान चेनई के साथ ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्द्धा में भी भारत को स्वर्ण जिता इतिहास रच दिया। सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जिताया। मुक्केबाजी में लवलिना बोरगोहन (75 किलो) परवीन हुड्डा (65 किलो) और अंकुश पांघाल (80 किलो) की त्रिमूर्ति ने अचूक घूंसों के प्रहार से अपने अपने वर्ग में स्वर्ण जिताया। पुरुषों की कुश्ती में अमन सहरावत और सुजीत कलकल ने स्वर्ण जीते।■

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद कृभको ने दिखाया दम

युवा सहकार टीम

देश की प्रमुख किसान सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) ने वित्त वर्ष 2025-26 में बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के साथ किसान हित, सहकारी विस्तार और नए क्षेत्रों में विकास की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं। संस्था ने इस अवधि में 824.68 करोड़ रुपये का टैक्स पूर्व मुनाफा अर्जित किया और अपनी सदस्य सहकारी समितियों को 20 प्रतिशत लाभांश देने की घोषणा की। कृभको की 46वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में यह जानकारी दी गई। इस दौरान संस्था की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। एजीएम में देशभर की सदस्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, निदेशक मंडल और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और बनास डेयरी के चेयरमैन शंकरभाई चौधरी को इस दौरान सहकारिता शिरोमणि और भगवान सिंह यादव को सहकारिता विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

कृभको चेयरमैन वी. सुधाकर चौधरी ने एजीएम में बताया कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद कृभको ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखा है। संस्था की कुल आय बढ़कर 16,401.36 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह 15,694.01 करोड़ रुपये थी। कृभको ने उर्वरक उत्पादन क्षेत्र में भी अपनी क्षमता और दक्षता को बनाए रखा। संस्था ने इस दौरान 21.34 लाख टन यूरिया का उत्पादन किया, जबकि यूरिया संयंत्र की क्षमता उपयोगिता 97.26 प्रतिशत रही। इसी अवधि में 12.39 लाख टन अमोनिया का उत्पादन किया गया और इसकी क्षमता उपयोगिता 99.36 प्रतिशत रही। किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृभको ने इस वित्त वर्ष में 45.85 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री की। 31 मार्च, 2026 तक कृभको से 9,672 सदस्य सहकारी समितियां जुड़ी हुई थीं।



वित्त वर्ष 2025-26 में टैक्स पूर्व मुनाफा 824.68 करोड़ रुपये और कुल आमदनी 16,401.36 करोड़ रुपये रहा

कृभको ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को भी विस्तार दिया है जिसमें नीम कोटेड यूरिया, जैव उर्वरक, कंपोस्ट, प्रमाणित बीज, हाइब्रिड बीज, जिंक सल्फेट और अन्य कृषि उत्पाद शामिल हैं। कृभको की सहायक कंपनियों ने भी इस दौरान मजबूत प्रदर्शन किया है। कृभको फर्टिलाइजर लिमिटेड (केएफएल) ने 2025-26 के दौरान 11.02 लाख टन यूरिया और 6.68 लाख मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया। केएफएल की क्षमता उपयोगिता क्रमशः 127.48 प्रतिशत और 133.16 प्रतिशत रही। कंपनी ने 14.40 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया। वहीं कृभको एग्री बिजनेस लिमिटेड (केएबीएल) ने कृषि उत्पाद व्यापार और निर्यात के क्षेत्र में विस्तार करते हुए 1,919.35 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया। इसमें घरेलू कारोबार 1,436.81 करोड़ रुपये और निर्यात कारोबार 482.54 करोड़ रुपये रहा।

यह सहकारी संस्था किसानों को बेहतर कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें आधुनिक कृषि तकनीक और टिकाऊ खेती से जोड़ने का काम भी कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में कृभको ने 8.99 लाख लीटर तरल जैव उर्वरक की बिक्री की। इसके अलावा 33,874 टन सिटी कंपोस्ट की मार्केटिंग और 1.67 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन एवं वितरण किया।

भविष्य की रणनीति के तहत कृभको अब कृषि क्षेत्र से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। यह भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की प्रमुख प्रवर्तक है। इसके अलावा यह नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (भारत टैक्सी) की भी प्रवर्तक है। ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में कृभको नई परियोजनाओं पर काम कर रही है। कृभको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के हजीरा और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में परियोजनाएं विकसित कर रही है, जिनके वित्त वर्ष 2026-27 में शुरू होने की संभावना है। ■

युवा सहकार हाईलाइट्स



नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी की टीम द्वारा इफको एवं गुजकोमासोल के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी को मासिक पत्रिका 'युवा सहकार' भेट की गई। पनामा सिटी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (आईसीए) की महासभा में श्री संघाणी ICA वैश्विक निदेशक मंडल में एट-लार्ज निदेशक के रूप में चुने गए। भारतीय सहकारिता क्षेत्र के लिए यह गौरवपूर्ण उपलब्धि है। यह उपलब्धि वैश्विक सहकारिता मंच पर भारत की बढ़ती सहभागिता और प्रभावी प्रतिनिधित्व को भी दर्शाती है। समस्त भारतीय सहकारिता परिवार की ओर से श्री संघाणी जी को हार्दिक बधाई एवं सफल, प्रेरणादायी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं।



नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी की टीम ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के उप प्रबंध निदेशक श्री रोहित गुप्ता (दाएं) से सार्थक मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सहकारिता क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी, युवा सशक्तीकरण तथा सहकारी क्षेत्र के माध्यम से रोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर उन्हें NYCS की मासिक पत्रिका 'युवा सहकार' की भेंट की गई। 'युवा सहकार' पत्रिका युवाओं और सहकारिता क्षेत्र के बीच संवाद एवं जुड़ाव का एक प्रभावी माध्यम है।

शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF EDUCATION
Government of India

nbt.india
एकः सूते सकलम्

महाराष्ट्र शासन

मुंबई पुस्तक महोत्सव

प्रवेश निःशुल्क

निःशुल्क पार्किंग

24-29 नवंबर 2026

प्रात: 11:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक

मुंबई विश्वविद्यालय, कलिना परिसर

मुख्य आकर्षण

पुस्तक मेला | साहित्यिक सत्र | बाल गतिविधियाँ | सांस्कृतिक कार्यक्रम | थीम प्रदर्शनी



www.mumbaibookfestival.com

98 207 008 88



महोत्सव सहयोगी aspect